



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 17 जुलाई, 1997/26 आषाढ़, 1919

No. 137]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 1997/ASADHA 26, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1997

**विषय: जर्मनी और कोरिया गणराज्य से एक्रिलोनाइट्रायल ब्यूटाडीन रबड़ (एनबीआर) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच—
अंतिम जांच परिणाम**

9/1/95-ए डी डी— वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसके सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क को पहचान, आकलन तथा बमूली एवं क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 को देखते हुए:

क. प्रक्रिया

1. नीचे वर्णित जांच-प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :—

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा जाएगा) दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या 9/1/95 -ए डी डी के द्वारा प्रारम्भिक जांच परिणाम अधिसूचित कर दिया था और संबद्ध पक्षों से निवेदन किया गया था कि वे प्रकाशन की तिथि से 40 दिन के भीतर लिखित रूप में अपने-अपने विचार व्यक्त करें।
- (ii) प्रारम्भिक जांच परिणाम की प्रति भेजते हुए सभी ज्ञात संबद्ध पक्षों से निवेदन किया गया था कि वे इस पत्र की तारीख से 40 दिन के भीतर प्रारम्भिक जांच-परिणाम पर अपने-अपने विचार अगर कोई हों, प्रस्तुत करें।
- (iii) प्राधिकारी ने प्रारम्भिक जांच परिणामों की एक-एक प्रति जर्मनी संघीय गणराज्य (जिसे इसके बाद जर्मनी कहा जाएगा) और कोरिया गणराज्य (जिसे इसके बाद कोरिया कहा जाएगा) के नई दिल्ली स्थित दूतावास को इस निवेदन के साथ भेजी थी कि निर्यातकों और अन्य संबद्ध पक्षों को प्रारम्भिक जांच परिणाम पर अपने-अपने विचार व्यक्त करने की सलाह दी जाए:
- (iv) प्राधिकारी ने दिनांक 14 फरवरी, 1997 को संबद्ध पक्षों के मौखिक रूप से विचार जानने के लिए सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की। सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षों से आग्रह किया गया था कि सुनवाई में मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत

(1)

किया जाए। भाग लेने वाले पक्षों को सलाह दी गई थी कि विरोधी पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रति लेकर उनके बारे में अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें। निम्नलिखित पक्षों ने सुनवाई में भाग लिया:

- याचिकाकर्ता, जी ए पी एल
- श्री वेंकटेश्वर इंद्र,
- पार्कमेन पालीमर लिमिटेड
- अखिल भारतीय रबड़ औद्योगिक संगठन
- इनारको लिमिटेड
- बेयर (इंडिया) लिमिटेड
- ऋषिरूप पालीमर प्रा. लिमि.,
- पुनीत रेजिन्स लिमि.,
- इन्देई पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमि.,
- कैमोप्लास्ट
- यम्बई कैमिकल एंड रबड़ प्रोडक्ट्स
- कोहिनूर इंडिया
- कैपैक्सल
- सी डी आर इन्टरप्राइजेज
- माइक्रो रबड़

- (v) उक्त नियम के नियम 16 के अनुसार, इस जांच परिणाम के लिए विचार किए गए सभी अनिवार्य तथ्यों/आधारों की जानकारी सभी ज्ञात संबद्ध पक्षों को दी गई। उस पर प्राप्त हुई टिप्पणी पर भी इन जांच-परिणामों में विचार किया गया।
- (vi) आम मुद्दों पर निर्यातकों, आयातकों और अन्य संबद्ध पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को संक्षिप्त रखने के उद्देश्य से दोहराया नहीं गया है। प्रारंभिक जांच परिणाम से पहले अनेक संबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए विचारों को भी इसी वजह से नहीं दोहराया गया है।
- (vii) जांच प्रक्रिया को केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई समय-सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है।
- (viii) प्राधिकारी ने इस अधिसूचना में गोपनीय जानकारी को दबा दिया है। लेकिन गोपनीय आंकड़े इस अधिसूचना में “***” के रूप में दर्शाए गए हैं।

ख. याचिकाकर्ता के विचार

2. याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक जांच परिणाम पर निम्नलिखित निवेदन किया है:—

- (क) कोरिया गणराज्य के मामले में सामान्य मूल्य और पाटन सीमा बहुत कम है। निर्यात मूल्य एवं निर्यातक द्वारा दावाकृत समायोजन और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई पाटनसीमा पर विचार करने पर कोरिया कुम्हो के मामले में सामान्य कीमत 1436.30 अमेरिकी डालर बनती है। यह सामान्य मूल्य प्रथमदृष्टया संदेहास्पद है। सामान्य मूल्य, उत्पादन लागत और निर्यात मूल्य की प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए क्योंकि इस मूल्य से पूरी लागत वसूल नहीं हो रही है।
- (ख) कोरिया गणराज्य के मामले में प्राधिकारी को कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत निर्धारित करने में दोहरी दलाली पर विचार करना चाहिए क्योंकि उसकी बिक्रियां कोरिया कुम्हो की एक ग्रुप कंपनी, कुम्हो एंड कंपनी इंक के जरिए की गई है।
- (ग) प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्कों की मात्रा निर्धारित करने के लिए जो उचित बिक्री-मूल्य निकाला है, उस पर याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:—
 - उचित बिक्री मूल्य को क्षमता उपयोग के इष्टतम स्तर पर आधारित नहीं होना चाहिए;
 - कच्चे माल की लागत वास्तविक आधार पर ली जानी चाहिए;
 - उपयोगिता लागत पर चर-लागत के रूप में विचार किया जाना चाहिए;

- सीधे श्रम की लागत पर घर-लागत के रूप में विचार किया जाना चाहिए;
- नकद छूट इत्यादि को घर-लागत के रूप में माना जाना चाहिए।
- उपभोक्ता की पहुंच लागत उचित विक्रय मूल्य निर्धारण के लिए संगत है जिसकी तुलना आयातों की पहुंच लागत के साथ की जानी चाहिए।

- (घ) याचिकाकर्ता घरेलू बाजार की मांग को पहले से ही पूरा कर रहा है और उसके पास कोरिया कुम्हों, बेयर और हुन्दई द्वारा निर्यातित जर्मन तथा कोरियन श्रेणी का माल है।
- (ङ) प्राधिकारी ने अनन्तिम पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश करते समय सीमाशुल्कों पर विचार न किए जाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। वर्ष 1997 के बजट प्रस्ताव में एन बी आर पर सीमाशुल्क को 52% से घटाकर 42% कर दिया गया है। इसलिए घरेलू उद्योग को, एन बी आर के पाटित आयातों से नए कीमत दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
- (च) हुन्दई पेट्रोकेमिकल कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद हुन्दई कहा जाएगा) द्वारा अपने घरेलू बाजार मूल्य और भारत को किए गए निर्यात के संबंध में किया गया दावा यह दर्शाता है कि हुन्दई के मामले में भी पाटन हुआ है।

(ग) निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

3. निर्यातकों और आयातकों द्वारा व्यक्त विचार संक्षेप में नीचे दिए गए हैं। निर्यातकों और आयातकों के एक समान विचारों को संक्षेप की दृष्टि से दोहराया नहीं गया है।

I. निर्यातक

(क) बेयर ए जी, जर्मनी

- (i) निर्यातक ने उक्त नियम के नियम 15 के अनुसार कीमत बचनबद्धता की अपनी इच्छा जाहिर की है और उस निर्यातक के मामले में जांच को स्थगित/समाप्त किए जाने का आग्रह किया है।
- (ii) चूंकि घरेलू बाजार में बिक्री के मामले में विपणन लागत एवं समर्थन लागत शामिल होती है; इसलिए इस बात को देखते हुए जर्मनी के सामान्य मूल्य की तुलना उस कीमत से नहीं की जा सकती है जिस कीमत पर भारत का सामान बेचा गया। बेयर ने अपनी बिक्री पत्र का एक हिस्सा थोक विक्रेता को बेचा था।
- (iii) बेयर ने जांच की अवधि के दौरान एक नया उत्पाद परव्यूनन एन टी 3445 बनाना शुरू किया और जांच की अवधि के दौरान उसको जो निर्यात कीमत थी, वह बाजार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आरम्भिक उच्च प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करने के रूप में एक आदर्श औद्योगिक क्रियाकलाप की परिचायक है।
- (iv) याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि जांच अवधि के दौरान कम्पनी ने माल डम्प किया है। याचिकाकर्ता ने यह विचार व्यक्त नहीं किया है कि पाटन जारी है।
- (v) जांच की अवधि इस प्रकार की जांच के लिए असामान्य रूप से कम है। जांच अवधि के दौरान ही संयोगवश बेयर ने एक नए प्रकार के एन बी आर को बाजार में प्रवेश कराया है और इस समय की कीमतें प्रारम्भिक चरण की कीमतें थीं।
- (vi) ग्राहकों को बेयर की औसत पहुंच लागत याचिकाकर्ता की पहुंच लागत के बराबर थी।
- (vii) जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को कोई क्षति नहीं हुई है। यह बात याचिकाकर्ता के उत्पादन में वृद्धि और भण्डार में कमी से जाहिर है। याचिकाकर्ता अपनी स्वयं की कमजोरियों के कारण स्थापित क्षमता का उपयोग करने में असफल रहा है। याचिकाकर्ता को क्षति इसलिए हुई है क्योंकि कच्चे मालों की कीमत में वृद्धि हुई है।
- (viii) इस बात को देखते हुए कि याचिकाकर्ता एन बी आर की कुछ किस्में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। शुल्क लगाने के प्रस्तावित आदेश में एन बी आर की सभी किस्मों को शामिल करना अनावश्यक है और इससे जांच का दायरा बढ़ जाएगा।
- (ix) प्रारम्भिक जांच-परिणाम के जे 1 के अन्तर्गत दी गई सारणी अपूर्ण है क्योंकि इसमें सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को नहीं दर्शाया गया है जैसा कि इससे पहले की कार्रवाई में सुझाया गया है।
- (x) याचिकाकर्ता ने खुद ही अपने बाजार हिस्से में 3% की वृद्धि दर्शाई है जबकि प्राधिकारी ने 6% की कमी पाई है। इस कमी से यह सुनिश्चित नहीं होता कि याचिकाकर्ता को कोई क्षति हुई है।
- (xi) याचिकाकर्ता ने अक्टूबर, 1994 में मूल्य में 10% वृद्धि की और सितम्बर, 1994 से अब तक 52% वृद्धि की है। इसलिए याचिकाकर्ता पर एन बी आर को अलाभकारी मूल्य पर बेचने का कोई दवाब नहीं है।

- (xii) याचिकाकर्ता भारत में एन बी आर का अकेला उत्पादक है। इष्टतम उत्पादन लागत और क्षमता उपयोग का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया गया है जो भारत को एन बी आर के अन्य निर्यातकों (जर्मनी को छोड़कर दूसरे देशों से) की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

ख. कोरिया कुम्हो पैट्रोकेमिकल कंपनी लिमि., कोरिया :

कोरिया कुम्हो पैट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड (इसके बाद इसे कोरिया कुम्हो कहा जाएगा) द्वारा मीथे तथा साथ ही इसके प्रतिनिधियों मैसर्स त्रिपरूप पोलिमर्स प्रा. लि. (इसके बाद इसे त्रिपरूप कहा जाएगा) के माध्यम से व्यक्त किए गए विचार संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है :—

समान वस्तुओं पर :—

- (i) प्राधिकारी ने जापान के विरुद्ध पाटन रोधी जांच से संबंधित अपनी पूर्ववर्ती जांच में यह निष्कर्ष निकाला था कि गैर-जापानी एन बी आर घरेलू एन बी आर के लिए एक “समान वस्तु” नहीं है;
- (ii) एन बी आर एक वस्तु नहीं है लेकिन वस्तुओं के एक समूह के लिए एक व्यापक शब्द माना जा सकता है;
- (iii) एन बी आर विश्व-भर में अपने भौतिक रूपों में उपलब्ध हैं, जैसे ठोस रूप में (बेल, शीट, पाउडर) तरल रूप (शुद्ध सामग्री, पायस रूप जैसे पानी के साथ लेटेक्स) प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि एन बी आर के सभी भौतिक रूप एक समान हैं, जो कि सही नहीं हैं;
- (iv) अनुकल्प के बारे में पैरा एफ (5) में प्राधिकारी के निष्कर्षों के संबंध में यह प्रमाणित करने का दायित्व याचिकाकर्ता का बनता है कि कोरियन एन बी आर ग्रेड याचिकाकर्ता के एन बी आर ग्रेड के समान है;
- (v) यह अनुमान जापान से संबंधित जांच परिणामों से लगाया जा सकता है; कि कोरियन एन बी आर, याचिकाकर्ता के एन बी आर के लिए एक समान वस्तु नहीं है;
- (vi) प्रारंभिक जांच के पैरा एफ (3) से जो य. निष्कर्ष निकाला गया है कि घरेलू उत्पादकों और विदेशी आपूर्ति के बीच अनेक प्रयोक्ताओं ने अपनी मांग में वृद्धि कर दी, उसका रिकार्ड में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है अथवा उक्त साक्ष्य टिप्पणी के लिए कोरिया कुम्हो को नहीं भेजा गया है ;
- (vii) विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा एफ (4) में निकाले गए निष्कर्ष का रिकार्ड में कोई साक्ष्य नहीं है अथवा उक्त साक्ष्य टिप्पणी के लिए कोरिया कुम्हो को नहीं भेजा गया है।

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर :—

- (i) याचिकाकर्ता ने कोरिया में सामान्य मूल्य के समर्थन में साक्ष्य नहीं भेजा है;
- (ii) प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँचों में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत राशियां प्रकट नहीं की हैं;
- (iii) प्राधिकारी ने कीमत सामायोजन और तुलना के संबंध में कोरिया कुम्हो द्वारा दिए गए निवेदन पर विचार नहीं किया है;
- (iv) भारत को चालू निर्यात कीमत अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता को कोरियन आयातों से भविष्य में वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है। प्राधिकारी को, पाटन रोधी शुल्क की सिफारिश करते समय जाँच अवधि के बाद के कारकों सहित सभी कारकों पर विचार करना होगा। प्राधिकारी को पाटन रोधी शुल्क का निर्धारण करते समय मामले की समीक्षा करनी चाहिए और उसे अद्यतन करना चाहिए। याचिकाकर्ता को 139 लाख रु. (1995-96) तथा 220 लाख रु. (अप्रैल—सितं.-1996) का लाभ हुआ बतलाया गया है।

याचिकाकर्ता वर्तमान में 91000/- रु. प्रति मी. टन कारखाना द्वारा कीमत पर बिक्री कर रहा है प्राधिकारी को अनेक हितबद्ध पार्टियों के हितों के विवेकपूर्वक संतुलन के लिए समझदारी और अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

क्षति पर :—

- (i) याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता द्वारा जाँच अवधि के लिए कोई आर्थिक आंकड़ें नहीं दिए गए थे;
- (ii) याचिकाकर्ता के तुलना पत्र से उसे हुई क्षति का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है;
- (iii) अलग-अलग आयात-सौदों की पहुँच लागत याचिकाकर्ता के दावों से अधिक थी;
- (iv) एन बी आर का कुछ भाग निर्यात के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए आयात किया गया था संबंधित देशों से आयातों की मात्रा का हिसाब लगाने के लिए निर्यात उत्पादन के लिए आयातित एन बी आर की मात्रा कुल आयातों में से घटा लेनी चाहिए। निर्यात उत्पादन के लिए आयात एक ऐसे बाजार में किए गए जहाँ याचिकाकर्ता अपने कारोबार के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है;
- (v) याचिकाकर्ता का कीमत क्रम करने का दावा इसके तुलनापत्र द्वारा प्रमाणित नहीं है, जो काफी अधिक बिक्री कीमतें दर्शाता है;

- (vi) प्रारंभिक जांच परिणामों और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध में अन्तर्विरोध है जैसा कि याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि उसे कम मूल्य वर्धित गैर एन बी आर मदों का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया गया जबकि प्राधिकारी ने यह पाया कि याचिकाकर्ता ने गैर एन बी आर मदों की बिक्री से और अपार लिमि. के व्यापार परिवर्तन से लाभ अर्जित किया है;
- (vii) चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही 87,500 प्रति मी. टन पर बिक्री कर रहा था जोकि जापान से आयात संबंधी जांच में प्राधिकारी द्वारा तय की गई उचित बिक्री कीमत से अधिक है, इसलिए इसे आगे राहत देना आवश्यक नहीं है।
- (viii) कोरिया से हुए निर्यातों से भारतीय बाजार की कीमतें कम नहीं हुई हैं।
- (ix) क्षति निर्धारण से संबंधित प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा "के" में दिया गया निष्कर्ष लिखित में बिना किसी साक्ष्य के है अथवा उक्त साक्ष्य टिप्पणी के लिए कोरिया कुम्हो को नहीं भेजा गया है;
- (x) रिकार्ड में यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि केवल कोरिया से हुए आयात में ही जांच अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- (xi) प्राधिकारी ने अपने निष्कर्ष में यह गलत कहा है कि कोरिया से एन बी आर के सी आई एफ निर्यात मूल्य में गिरावट आई;
- (xii) यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि जांच अवधि के दौरान भारत में हुए कुल आयातों में कोरियन आयातों का हिस्सा बढ़ा है;
- (xiii) बिक्री कीमतों के संबंध में पैरा "के"-4 (डी) में दिए गए निष्कर्ष का लिखित में कोई साक्ष्य नहीं है;
- (xiv) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के क्षमता उपयोग के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया है।
- (xv) घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करते समय प्राधिकारी द्वारा कथित डम्पिंग के अतिरिक्त अन्य कारकों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। निम्नलिखित कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई;
- (क) पिछले वित्तीय वर्ष 1993-94 से आगे लाई गई संचयी हानियां;
- (ख) याचिकाकर्ता द्वारा संयंत्र की गलत जगह पर स्थापना क्योंकि संयंत्र ब्यूटाडीन की आपूर्ति के स्रोत के नजदीक नहीं है, जिसकी वजह से 1000/- रु. प्रति मी. टन की सीमा तक ब्यूटाडीन की अधिक लागत हुई है।
- (ग) बिजली की 1215 किलो वाट प्रति मी. टन की मानक खपत की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान बिजली की खपत 9.7% अधिक थी ;
- (घ) याचिकाकर्ता को उपभोग की गई प्रति मी. टन कच्ची सामग्री से एक मी. टन उत्पाद का उत्पादन करना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने 9607 मी. टन कच्ची सामग्री का उत्पादन किया और 8,895 मी. टन का उत्पादन किया जिसके परिणामस्वरूप 1994-95 के दौरान 162.55 लाख रु. मूल्य की लगभग 547 मी. टन कच्ची सामग्री का अपव्यय हुआ;
- (ङ) दिनांक 4 फरवरी, 1997 के सी ई जी ए टी आदेश सं. 148-154/97-ए, के अनुसार मई और जून, 1994 के दौरान याचिकाकर्ता ने कम उत्पादन किया जिसके लिए समायोजन प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।
- (च) याचिकाकर्ता के पास लघु क्षमता का एक संयंत्र है। सामान्यतया, ऐसे संयंत्रों की अन्तर्राष्ट्रीय रूप से 50000 मी. टन न्यूनतम व्यवहार्य क्षमता होती है। वर्ष 1994-95 के लिए याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट विश्लेषण यह प्रकट करता है कि इसकी विनिर्माण लागत से बिक्री वसूली का अनुपात 27.13% था और कच्चे माल की लागत से बिक्री वसूली का अनुपात 56.83% था यदि संयंत्र क्षमता अधिक होती तो उस स्थिति में उत्पादन लागत पर्याप्त मात्रा में कम होती।
- (छ) ऊपर दिए गए सभी कारक यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता को जर्मनी और/अथवा कोरिया से हुए आयातों के अलावा अन्य कारकों से लगभग 11210 रु. प्रति मी. टन क्षति हुई।

अन्य :—

- (i) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(6) के अनुसार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के सभी प्रावधान इस जांच के लिए लागू हैं। इसलिए मार्च, 1995 की समाप्ति से छः महीने की समाप्ति के बाद याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई कोई शिकायत सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 के अनुसार निर्धारित सीमा अवधि द्वारा वर्जित है। इसलिए जर्मनी के विरुद्ध दायर की गई याचिका समय-वर्धित है। इस संबंध में त्रुटिरूप द्वारा 1990 (49) ई एल टी 541 के एक्साइज लॉ टाइम्स में प्रतिवेदित सी ई जी ए टी निर्णय का भी उल्लेख किया गया है।
- (ii) याचिकाकर्ता के पास देश में एन बी आर की पूरी मांग को पूरा करने की क्षमता का अभाव है;
- (iii) प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकालने में भूल की है कि विचार की गई जांच की अवधि नियमों के अनुसार है। जांच की अवधि के संबंध में नियमों में कोई नियम नहीं रखा गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई नियम नहीं है जो याचिकाकर्ता द्वारा मनमाने ढंग से चुनी गई अवधि में जांच के लिए प्राधिकारी को बाध्य करे। सामान्यतः जांच के लिए एक वर्ष की समय अवधि पर विचार किया जाता है;

- (iv) नियमों के नियम 2 (बी) में "उत्पादकों" शब्द में "उत्पादक" शामिल नहीं है। नियम 2(बी) से यह स्पष्ट है कि घरेलू बाजार में कम से कम दो उत्पादक होने चाहिए ताकि उन्हें घरेलू उद्योग के रूप में माना जा सके। चूंकि याचिकाकर्ता भारत में एन बी आर का एकमात्र उत्पादक है इसलिए यह घरेलू उद्योग की पात्रता नहीं रखता।
- (v) याचिकाकर्ता ने एन बी आर की केवल बेल किस्म की डंपिंग का आरोप लगाया;
- (vi) कोरिया के विरुद्ध लिखित शिकायत का कोई साक्ष्य नहीं है।
- (vii) प्राधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों द्वारा दी गई सूचनाओं को गोपनीय नहीं रखा है। कोरिया कुम्हों के मामलों में सामान्य मूल्य प्रारंभिक जांच परिणामों से निकाला जा सकता है, जबकि प्राधिकारी ने निर्यात कीमत, कीमत समायोजन तथा डंपिंग मार्जिन प्रकट कर दिया है।
- (viii) पैरा सी (सी) निर्यात कीमत और कीमत समायोजन पैरा सी (डी) कोरिया से आयातों की मात्रा (के 4)(ए) (कोरिया से आयातों की मात्रा में वृद्धि) के 4 (डी) (सी आई एफ निर्यात कीमत में गिरावट) के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणामों में तथ्यों संबंधी गलतियां हैं (हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के संबंध में) इन तथ्यों की गलती से यह स्पष्ट होता है कि लापरवाही बरती गई और गलत जांच की गई;
- (ix) प्राधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया है क्यों कि सुनवाई 12-6-1996 को आयोजित सार्वजनिक आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई।
- (x) प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार उस मद की पहचान तक ही सीमित है जिसका भारत में आयात किया गया है और जिस पर पाटन रोधी जांच के लिए विचार किया जा सकता है;
- (xi) एच एस आर उत्पादन के संबंध में कोई आर्थिक आंकड़े जैसे उत्पादन स्टॉक बिक्री मात्रा और बिक्री कीमतें शेषरूप को टिप्पणी के लिये भेजे जाने चाहिए।
- (xii) प्राधिकारी को चाहिए कि वह याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचाने वाले कथित डंपिंग के अतिरिक्त अन्य कारकों का निर्धारण करे और उचित छूट प्रदान करें।
- (xiii) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करने के लिए जर्मनी और कोरिया आर पी से हुए आयातों को एक साथ मिलाकर गलती की है। कोरिया आर पी से हुए आयातों में गिरावट की प्रवृत्ति, कोरिया आर पी से स्थायी निर्यात कीमत और कोरिया आर पी से निर्यातकों द्वारा कीमतों को कम नहीं किए जाने जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी पर आधार निर्धारण करना अनुचित होगा;
- (xiv) पाटन रोधी शुल्क लगाने से भारत में एन बी आर के उपभोक्ताओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उनकी कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ेगा;
- (xv) एन बी आर का चूर्ण अथवा तरल रूप एक ही संयंत्र और उपकरण से नहीं बनाया जा सकता है; जबकि बेल किस्म का एन बी आर बनाया जा सकता है।

ग. हुन्दई पेट्रोकेमिकल कं. लिमि.

- (i) हुन्दई ने यह दावा किया कि इसने जांच अवधि के दौरान कोई सामग्री निर्यात नहीं की और कंपनी ने केवल जांच अवधि के बाद ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया,
- (ii) याचिकाकर्ता ने हुन्दई द्वारा निर्यात किए गए एन बी आर पर पाटन रोधी शुल्क लगाने की मांग नहीं की है;
- (iii) अमरीकी डालर 1475 की निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, जिस पर कंपनी ने भारत को निर्यात किया है; हुन्दई से हुए निर्यातों की पहुंच कीमत याचिकाकर्ता की कारखाना-गत कीमत से अधिक है,
- (iv) हुन्दई ने कोरिया में अपने कुछ ग्राहकों को यू. एस. डालर 1450-1500 प्रति मी. टन की कीमतों पर बिक्री की है;

II. आयातक और अन्य इच्छुक पार्टियां

1. याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित एन. बी. आर. की गुणवत्ता संदर्भित देशों द्वारा उत्पादित एन. बी. आर. की गुणवत्ता की तुलना में घटिया और अमंगत है। जापान से आयातित एन. बी. आर. पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने के बाद भी आयातकों को जापान से एन बी आर का आयात करने के लिए विवश किया जाता है। इससे इनकी उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। जर्मनी और कोरिया से किए गए आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने से याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित एन बी आर की गुणवत्ता में और ज्यादा गिरावट आएगी।

2. संदर्भित देशों से आयातित और याचिकाकर्ता द्वारा बेचे गए एन बी आर के ग्रेड के संबंध में मूल्य की तुलना करनी ही होगी। जहाज से माल उतारे जाने के बाद उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली वस्तु के मूल्य के संदर्भ में तुलना करनी ही होगी। अधिकारी ने घरेलू बाजार में औसत सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य की तुलना करके पाटन सीमा की गणना की है।

3. याचिकाकर्ता ने प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने पर हर बार अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि की है।

4. पाटन का आरोप करीब दो वर्ष पुराना है और इस समय प्रति-पाटन शुल्क लगाने से बदली हुई परिस्थितियों में कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

5. प्रति पाटन शुल्क लगाया जाना रबड़ उद्योग के हित में नहीं होगा एवं यह मूल्य तथा गुणवत्ता के रूप में निर्यात को प्रभावित करेगा।

6. भारत में एन बी आर की मांग याचिकाकर्ता के उत्पादन से काफी ज्यादा है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में मांग और आपूर्ति के बीच भारी अन्तर है। इससे देश में छोटे स्तर के एककों के हित प्रभावित होंगे।

7. प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने से याचिकाकर्ता द्वारा मूल्यों में वृद्धि की जाएगी तथा बाजार में वस्तुओं की कमी होगी।

घ. अधिकारी द्वारा जाँच

4. याचिकाकर्ता, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों की जाँच की गई और उन पर विचार किया गया तथा जहाँ भी उपयुक्त समझा गया उन पर इसके बाद कार्रवाई की गई।

यह कहना गलत है कि कोरिया आर. पी. के विरुद्ध कोई लिखित शिकायत नहीं थी। अधिकारी ने पत्र के उत्तर में याचिकाकर्ता ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया कि “कोरिया से आयात पाटन कीमतों पर हुआ है”। याचिकाकर्ता ने कोरिया आर. पी. के निर्यातक (निर्यातकों) के नाम और पते निरपेक्ष रूप में एवं भारत में कुल आयात की तुलना में एन बी आर की कुल खपत, कोरिया आर. पी. से एन बी आर के आयात के विस्तृत विवरण और कोरिया आर पी के निर्यातकों द्वारा पाटन के निर्धारण से संबंधित अन्य विवरण तथा/या घरेलू उद्योग को हुई क्षति के विस्तृत विवरण दिए हैं। चूंकि याचिकाकर्ता ने जाँच संबंधी अन्य सम्बद्ध विवरण पहले ही दे दिए गए थे। इसलिए कोरिया आर पी के विरुद्ध लगाए गए आरोप के संबंध में याचिका को उचित रूप से लिखित प्रमाणयुक्त माना गया।

5. बेयर ए. जी. द्वारा जिस कीमत वचनबद्धता की पेशकश की गई उसे अधिकारी अव्यवहारिक मानते हैं और इस प्रकार बेयर ए. जी. के बारे में निश्चित निर्धारण की कार्रवाई की है।

6. इस तर्क में कोई दम नहीं है कि याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करते समय कोई आर्थिक आँकड़े प्रस्तुत नहीं किए थे। अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जाँच शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी द्वारा माँगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत कर दिए थे।

7. जाँच की अवधि का सुझाव देने के लिए नियमों में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। तथापि, यह सुझाव देने के परोक्ष संदर्भ उपलब्ध हैं कि जाँच की अवधि 6 महीने से कम अवधि की होनी चाहिए। प्रतिपाटन शुल्क लगाने के लिए पाटन हुआ था या नहीं, इसकी जाँच करने के लिए छह महीने की अवधि को पर्याप्त माना जाता है।

8. सार्वजनिक सुनवाई संबंधी नियम निम्नानुसार हैं :—

“प्राधिकृत अधिकारी किसी इच्छुक पक्ष या उसके प्रतिनिधि को जाँच से संबंधित सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन ऐसी मौखिक सूचना पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तभी विचार किया जाएगा जबकि बाद में इसे लिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाए”

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :—

o किसी भी पक्ष को मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि अधिकारी द्वारा इसकी अनुमति न दी जाए ;

o पार्टी द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक सूचना पर तब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे लिखित रूप में पुनः प्रस्तुत न किया जाए।

उपर्युक्त नियम का सार यह है कि प्राधिकारी द्वारा केवल लिखित सूचना पर विचार किया जाएगा। चूंकि विभिन्न इच्छुक पार्टियों द्वारा दी गई लिखित सूचना प्राधिकारी के पास पहले से ही उपलब्ध थी, इसलिए दूसरी सार्वजनिक सुनवाई किए बिना प्राधिकारी ने प्रारम्भिक जाँच परिणामों पर आगे की कार्रवाई करना उपयुक्त माना। उपर्युक्त के बावजूद अधिकारी अभी जाँच किए जा रहे सभी मामलों में प्रारम्भिक जाँच-परिणाम के बाद ही अनवरत रूप से सार्वजनिक सुनवाई कर रहे हैं। इसके अलावा प्राधिकारी ने 14 फरवरी, 1997 की सार्वजनिक सुनवाई की अनुमति दी और इसलिए इस संबंध में दिए गए तर्क पर ध्यान किए जाने की जरूरत नहीं है।

9. प्रति-पाटन शुल्कों का भुगतान करने से अलग करने के हुन्दई के अनुरोध के संबंध में अधिकारी यह नोट करते हैं कि हुन्दई को छोड़ना नियमानुसार नहीं होगा चूंकि इस पार्टी ने जाँच-अवधि के दौरान भारत को किसी सामग्री का निर्यात नहीं किया। वास्तव में हुन्दई के अनुसार, इसने जाँच अवधि के बाद ही घाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत की। चूंकि हुन्दई ने जाँच-अवधि के दौरान भारत को निर्यात नहीं किया, इसलिए इस पर नियम 22 लागू

होता है जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि अधिकारी किसी निर्यातक (निर्यातकों) या उत्पादक (उत्पादकों) के लिए वैयक्तिक पाटन सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से समीक्षा कर सकता है, जिसने जाँच-अवधि के दौरान निर्यात नहीं किया। इस प्रकार, हुन्दई जाँच के सम्पन्न होने के बाद अपने को अलग किए जाने का अधिकारी से अनुरोध कर सकता है।

चूँकि हुन्दई ने जाँच-अवधि के दौरान एन बी आर का निर्यात नहीं किया है, इसलिए याचिकाकर्ता का यह तर्क कि कम्पनी ने अपने एन बी आर का भारतीय बाजार में पाटित किया, सही नहीं है।

अधिकारी ने इसकी जाँच की है कि क्या निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का पाटन उक्त देशों से जाँच अवधि के दौरान किया गया। अधिकारी ने जाँच-अवधि के बाद पाटन या क्षति की जाँच नहीं की है। अगर जाँच के बाद की अवधि में परिस्थितियाँ बदली, तब इच्छुक पक्ष नियमानुसार समीक्षा का अनुरोध कर सकता है। इसके बावजूद, यह कहना गलत है कि याचिकाकर्ता ने लगातार पाटन करने का दावा नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने विभिन्न पत्रों के द्वारा लगातार पाटन का निवेदन करते हुए अधिकारी से जल्दी जाँच/प्रतिपाटन शुल्कों की सिफारिश करने का अनुरोध किया है।

12. बेयर के इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता ने जर्मनी से लगातार डम्पिंग करने का दावा नहीं किया है, प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि उन्होंने इस बात की जाँच कर ली है कि विचाराधीन उत्पाद की जाँच अवधि के दौरान संदर्भित देशों से निर्यातकों द्वारा डम्पिंग की गयी। प्राधिकारी ने जाँच अवधि के बाद हुई डम्पिंग अथवा क्षति के बारे में कोई जाँच नहीं की है यदि जाँच अवधि के बाद परिस्थितियाँ बदली हैं तो कोई इच्छुक पार्टी कानून के अनुसार पुनरीक्षा का अनुरोध कर सकती है। इसका यह कहना गलत है कि याचिकाकर्ता ने लगातार डम्पिंग होने का दावा नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने अपने विभिन्न पत्रों में लगातार डम्पिंग का दावा करते हुए प्राधिकारी से शीघ्र प्रतिपाटन शुल्क की जाँच/इसकी सिफारिश करने का अनुरोध किया है।

प्रति-पाटन जाँच के लिए 6 महीने की अवधि को उचित अवधि माना जा सकता है। यद्यपि यह प्रशंसनीय है कि बेयर का निर्यात मूल्य नए उत्पाद की शुरुआत का प्रतिबिम्ब हो सकता है, तथापि यह प्रतिपाटन जाँच के लिए अपसंगिक है।

प्राधिकारी द्वारा तैयार किए गए अनिवार्य तथ्यों को उजागर किया जाना :

क. संबंध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियाँ :

- I. मैं पुनीत रेजिन्स लिमि. ने प्राधिकारी द्वारा घोषित तथ्यों के प्रत्युत्तर में दावा किया कि प्राधिकारी द्वारा लगाया गया पहुँच मूल्य गलत है। वास्तविक रख-रखाव शुल्क 3% है न कि 2% जैसा कि प्राधिकारी ने माना है। मैं, ऋषिरूप ने तर्क दिया कि रख-रखाव खर्च को 5% माना जाना चाहिए।
- II. घरेलू बाजार में विक्रय मूल्य पर विज्ञापन लागत, अशोध्य ऋण दान राशि कार खर्च और मनोरंजन खर्च के लिए कटौती की जाए क्योंकि ये सभी प्रकार से संश्लिष्ट रबड़ की केवल घरेलू बिक्री पर ही दिए गए हैं।
- III. ऋषिरूप ने तर्क दिया है कि उचित बिक्री मूल्य के निर्धारण में श्रम और उपयोगिता लागत का चर लागत के रूप में नहीं मानना सही नहीं है। पार्टी ने आगे कहा है कि बहरहाल 40% या 60% या 80% क्षमता पर काम कर रहे संयंत्रों में सीधे श्रम, ऊर्जा और अन्य उपयोगी सेवाएँ जैसे कि स्टीम की अतिरिक्त लागत समानुपात में नहीं बढ़ती या बदलती हैं।
- IV. बेयर का विचार था कि याचिकाकर्ता का एकाधिकार है और याचिका प्रतिस्पर्धा हटाने का एक प्रयास है। पार्टी ने 30-9-1996 को समाप्त छमाही के अपरिष्कृत वित्तीय परिणामों (अन्तिम) का हवाला दिया है जो यह दर्शाते हैं कि वर्ष 1995-96 की संगत अवधि की तुलना में वर्ष 1996-97 की प्रथम छमाही में याचिकाकर्ता का लाभ बढ़ा है। पार्टी ने तर्क दिया है कि वास्तव में याचिकाकर्ता अपनी एन बी आर क्षमता का व्यापक विस्तार करने की योजना बना रहा है।
- V. बेयर ने दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा क्षमता का उपयोग न किए जाने का कारण तत्समय वांछित कच्चे मालों का अभाव था। पार्टी ने इस प्रयोजन से याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला दिया है।
- VI. प्राधिकारी का उद्देश्य या कार्य याचिकाकर्ता के लाभांश की मात्रा को सुनिश्चित करना नहीं है।
- VII. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि :
 - निर्यातकों ने कोरिया गणराज्य के मामले में घरेलू बाजार में बिक्री मूल्य जो मूल्य समायोजन का दावा किया है वह गलत है। टैरिफ वापसी के वास्तविक वापसी के लिए रोका जाना चाहिए क्योंकि कच्चे माल की खरीद घरेलू स्त्रोतों से की गई है। कोरिया कुम्हो की मुख्य बिक्री निर्यात बाजार में हुई है और इसलिए कोरिया कुम्हो को घरेलू बाजार की अपेक्षा विदेशों में ग्राहकों के पास जाने पर अधिक खर्च करना चाहिए।
 - अन्तर्देशीय भाड़े पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कोरिया कुम्हो ने अपनी वास्तविक कीमत-बसूली दी है जो सम्भवतः अन्तर्देशीय भाड़े का हिसाब निकालने के बाद की रकम है। याचिकाकर्ता ने मूल्य समायोजन के संबंध में कोरिया कुम्हो ने अन्य दावों पर विवाद खड़ा कर दिया है।
 - कारखानागत उचित बिक्री मूल्य की तुलना आयात के पहुँच मूल्य के साथ करना गलत है। जहाँ उचित बिक्री मूल्य कारखानागत है वहीं पहुँच मूल्य में दलाली और अन्य खर्च शामिल हैं। निर्यातकों ने भारत में एक प्रतिशत उतराई शुल्क वास्तविक रूप में खर्च नहीं किया है इसे केवल सीमा शुल्क की गणना करने के लिए किया जा सकता है।

(ख) प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य तथ्यों के उजागर संबंधी टिप्पणियों की जाँच

- I. प्राधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि इस समय इच्छुक पक्षों द्वारा दिए गए किसी नए साक्ष्य/तर्क/अनुरोध पर विचार करना उचित नहीं होगा। इसलिए तथ्यों के उजागर में किए विवरण अनिवार्य तथ्यों को प्रकट करने वाली टिप्पणियों पर ही इस पैरा में कार्रवाई की गई है।
- II. कोरिया कुम्हों के संबंध में घरेलू बाजार में बिक्री मूल्य पर रख-रखाव, शुल्क की गणना, उत्तराई शुल्क का भुगतान, विज्ञान लागत के कारण कटौती, अशोध्य ऋण, दान, कार खर्च और मनोरंजन व्यय के संदर्भ में इच्छुक पार्टियों द्वारा पूर्व में कोई टिप्पणियाँ नहीं की गई हैं। और इसलिए उन्हें अस्वीकार किया जाता है। अगर सूचना महत्वपूर्ण मानी जाती है तो इच्छुक पार्टी जाँच के समाप्ति के बाद किसी भी समय पुनरीक्षा का आग्रह कर सकती है।
- III. ऋषिरूप का यह तर्क कि क्या संयंत्र 40% या 60% या 80% क्षमता पर कार्यरत है, प्रत्यक्ष श्रम, ऊर्जा और अन्य उपयोगी सेवाएँ जैसे, भाप पर अतिरिक्त लागत में वृद्धि नहीं होती है अथवा इसी समानुपात में कोई अन्तर नहीं पड़ता है, को अस्वीकार नहीं किया जाता है। यद्यपि प्राधिकारी ने वास्तविक क्षमता उपयोगी की तुलना क्षमता उपयोगी के चरम स्तर से किया है। ताकि इस पर विचार किया जा सके कि पाटन सीमा से कम शुल्क लगाना घरेलू उद्योग की हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- IV. उत्तराई शुल्क के समायोजन के संबंध में प्राधिकारी ने आयातों की उत्तराई कीमत का निर्धारण करने के लिए एक प्रतिशत उत्तराई शुल्क और 2 प्रतिशत संचालन शुल्क लगाने पर हमेशा विचार किया है। ऋषिरूप और पुनीत रेजिन्स के क्रमशः 5% और 3% संचालन शुल्क के दावे के संबंध में, प्राधिकारी इस बात को नोट करते हैं कि संचालन शुल्क एवं एकल आयात कारोबार के आधार पर संचालन शुल्क का निर्धारण करना उचित नहीं हो सकता है।

(च) विचाराधीन उत्पाद

15. विचाराधीन उत्पादन, जिसकी जाँच पाटन के लिए की गई, उसे प्रारम्भिक जाँच परिणाम में परिभाषित किया गया है, जो कि सेटैक्स को छोड़ कर अपने सभी रूपों में एफ़्रीलोन ट्राइल बुटाडीन रबड़ (नाइट्रील रबड़ और एन बी आर के नाम से भी पुकारा जाता है और जिसे इसके बाद एन बी आर कहा जाएगा) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जर्मनी और कोरिया आर पी के उद्गम वाली आयातित वस्तुओं को वाणिज्यिक और तकनीकी दोनों रूपों में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने योग्य थी। वर्तमान जाँच के क्षेत्र की जाँच शुरू करने के नोटिस में परिभाषित किया गया था। याचिकाकर्ता ने डम्प किए जा रहे उत्पाद को "एफ़्रीलोनी ट्राइल बुटाडीन रबड़" अथवा एन बी आर के रूप में भी वर्णित किया गया है। तथा ऐसी व्याख्या करना गलत होगा कि याचिका सिर्फ एन बी आर की बेल किस्म के लिए थी।

अनेक संबद्ध पक्षों ने दावा किया है कि भारत में कई ग्रेडों का उत्पादन नहीं किया जाता है। ऋषिरूप ने प्राधिकारी से एन बी आर के कुछ ऐसे ग्रेडों को जाँच से अलग रखने की मांग की जिनका जाँच अवधि के दौरान भारत में आयात नहीं किया गया था। प्राधिकारी ने इस बात को नोट किया कि केवल उन किस्मों को जाँच के दायरे से बाहर रखा जा सकता है जिनका जाँच अवधि के दौरान पाटन नहीं किया गया था। चूंकि जाँच की अवधि के दौरान इन ग्रेडों का आयात नहीं किया गया था इसलिए पाटन नहीं किए जाने की बात न तो साबित होती है और न अमान्य है इसलिए प्राधिकारी के लिए यह उचित होगा कि यह किसी निर्यातक के जाँच के दायरे से बाहर रखने के किसी निश्चित प्रस्ताव पर विचार करें बशर्ते कि निर्यातक यह साबित करे कि संदर्भित ग्रेड का निर्यात भारत को तथाकथित गैर पाटित मूल्यों से कम मूल्य पर और अलाभकारी मूल्य पर नहीं किया गया है। चूंकि ऋषिरूप ने यह प्रमाणित किए बिना ही जाँच से बाहर रखने के लिए मांग की है कि उक्त ग्रेडों को भारत में पाटित नहीं किया गया है इसलिए ऋषिरूप के प्रतिवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। प्राधिकारी विचाराधीन उत्पादन से संबंधित प्रारम्भिक जाँच परिणामों के पैरा 16 की पुष्टि करते हैं।

16. समान वस्तुएं तथा घरेलू उद्योग

10. इस तर्क में दम नहीं है कि भारत में एन बी आर के एकमात्र उत्पादक होने के कारण याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग नहीं है। नियम 2 (ख) घरेलू उद्योग को उन घरेलू उत्पादकों के रूप में परिभाषित करता है जिनका सामूहिक उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा होता है। नियम में किसी विशेष प्रावधान के अभाव में कर्ता के बहुवचन में एकवचन भी शामिल होगा।

11. यह तर्क कि जापान के विरुद्ध प्रतिपाटन जाँच से संबंधित जाँच परिणाम में यह निष्कर्ष निकला कि गैर जापानी एन बी आर घरेलू एन बी आर के समान वस्तु नहीं है, के समर्थन में कोई तर्क या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। किसी विशेष मामले में की गई टिप्पणियाँ, उम विशेष मामले के तथ्यों के रेकार्डों पर आधारित हैं, और अन्य मामलों में उन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

12. "वस्तु" शब्द की व्याख्या एक मद के रूप में करना गलत है। "वस्तु" शब्द को इसके बहुवचन रूप में समझा जाना चाहिए। उदाहरण-स्वरूप सोना एक वस्तु है यद्यपि यह 24, 22, 20, 18 कैरेट इत्यादि की शुद्धता में उपलब्ध है। यह कहना गलत होगा कि ये सभी अलग-अलग वस्तुएँ हैं चूंकि इन सभी किस्मों के कच्चे माल का संघटन अलग-अलग है और इनकी कीमतों में काफी भिन्नता रहती है। 24 कैरेट के सोने की तुलना 18 कैरेट के सोने के साथ करना भी उचित नहीं होगा। अगर इन विभिन्न प्रकार/किस्म/ग्रेड के सोने को भारत में आयातित किए जाने के बाद और जाँच किए जाने के लिए तुलना करनी हो तो वह आयातित सोने की तुलना पर कैरेट तथा निर्यातक के घरेलू बाजार में बेचे गए सोने के आधार पर होगी। इसी प्रकार, भारत में आयातित 24 कैरेट के सोने की तुलना भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए 24 कैरेट के सोने के साथ करनी होगी। तथापि तथ्य यही रहेगा कि सोने

के सभी प्रकारों पर एक वस्तु के रूप में विचार करना होगा। इसलिए एक वस्तु की विभिन्न किस्मों/ग्रेडों/रूपों में सिर्फ तुलनीय के साथ ही तुलना करने की जरूरत है और इसका अर्थ यह नहीं कि ये अलग-अलग वस्तुएँ हैं।

13. विश्व भर में एन बी आर विभिन्न रूपों में जैसे कि टोस और द्रव रूप में बनाया जाता है तथापि, यह कहना गलत है कि अधिकारी ने प्रारम्भिक जाँच-परिणामों में यह देखा कि एन बी आर के सभी भौतिक रूप एक ही हैं। एन बी आर के विभिन्न रूपों के लिए अधिकारी को केवल तुलनीय रूपों/ग्रेडों की तुलना करनी होती है। उदाहरणस्वरूप अधिकारी को कोरिया से के एन बी 35 एल एन बी आर के आयात की तुलना याचिकाकर्ता के प्रतिस्थापन योग्य ग्रेड के साथ करनी है। इसी प्रकार, बेयर एजी के पेरुबन एन टी 3445 ग्रेड के साथ याचिकाकर्ता के प्रतिस्थापन योग्य ग्रेड के बीच तुलना करनी अपेक्षित है। अधिकारी ने प्रारम्भिक जाँच-परिणामों में यह निर्णय नहीं लिया कि बेयर ए जी या कोरिया कुम्हो के सभी ग्रेड एन टी 3445 या के एन बी 35 एल के प्रतिस्थापन योग्य हैं। जाँच के दायरे में एन बी आर पर विचार करने या यह समझने कि कोरिया आर पी तथा/या जर्मनी से आयातित एन बी आर समान वस्तु है का अर्थ यह नहीं कि अधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि संदर्भित देशों से आयातित सभी ग्रेड या याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित सभी ग्रेड एक समान हैं।

14. अन्य ग्रेड के एन बी 35 एल के प्रतिस्थापक होने के बारे में प्राधिकारी का विचार है कि निर्यातक ने नियमों के अन्तर्गत “समान वस्तुओं” शब्द की परिभाषा को व्याख्या करने में गलती की है। प्राधिकारी ने प्रारम्भिक जाँच परिणामों में “समान वस्तुओं” की परिभाषा को पुनः प्रस्तुत किया है। नियम 2(घ) के अन्तर्गत “समान वस्तुओं” का अर्थ ऐसी वस्तु से है जो कि भारत में डम्पिंग हेतु जाँच की जा रही वस्तु की सभी रूपों में मिलती-जुलती या समान है, या ऐसी वस्तु की अनुपस्थिति में ऐसी वस्तु जो कि सभी रूपों में भले ही समान नहीं है, लेकिन जिसके गुण जाँच की जा रही वस्तुओं के काफी मिलते-जुलते हैं।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियम 2(घ) का अर्थ यह नहीं है कि आयातित वस्तुओं तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं का स्थानापन्न अवश्य किया ही गया है और इसलिए यह “समान वस्तु” के कहलाने के योग्य है। इस मामले में स्थापन होने की योग्यता न कि स्थानापन्न होना उपर्युक्त परिभाषा का मूल कारण है। इस संबंध में हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाया गया तर्क यह नहीं है कि ये दोनों वस्तुएँ स्थानापन्न योग्य नहीं हैं।

इस तथ्य के बावजूद कि स्थानापन्न होने की योग्यता न कि स्थानापन्न होना मूल चिन्ता है, यह सुझाव देने के पर्याप्त प्रमाण हैं कि कुछ आयातकों ने अपनी आवश्यकताओं को घरेलू उत्पादन, जर्मनी, कोरिया और जापान के आयातों के बीच स्थानापन्न किया है। उदाहरण स्वरूप, मैसर्स संजय इन्टरनेशनल, कोहिनूर, ए वी इण्डस्ट्रीज हेतमपुरिया, गौरव इण्टरनेशनल ने एन बी आर का आयात कोरिया कुम्हो तथा जर्मनी से तथा/या जापान से किया। मैसर्स बसन्त रबर ने एन बी आर कोरिया कुम्हो से तथा याचिकाकर्ता से भी खरीदा इसके साथ-साथ, यह तथ्य कि पिछली अवधि की तुलना में जाँच अवधि के दौरान जर्मनी से आयातों में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई, स्पष्ट रूप से यह बताता है कि बड़े हुए आयात ने अन्य स्रोतों से की गई आपूर्ति का स्थान लिया। इस प्रकार इस संबंध में गत वर्ष से विकास नहीं किया।

16. इस संबंध में सभी तर्कों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के गुण उन वस्तुओं से काफी मिलते-जुलते हैं जिनकी जाँच की जा रही है और इस प्रकार नियम 2(घ) के अन्तर्गत परिभाषा में निर्धारित गुणों को पर्याप्त रूप से पूरा करते हैं। अधिकारी विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तुओं से संबंधित प्रारम्भिक जाँच-परिणामों के पैरा ड और च की पुष्टि करते हैं।

च. सामान्य मूल्य

17. धारा 9 के (1) (ग) के अन्तर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है :—

- (1) व्यापार के सामान्य क्रम में मिलती-जुलती वस्तु के लिए तुलनात्मक कीमत, जब वह निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र में उपभोग के निमित्त हो, जैसा कि उप-धारा (6) के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारण किया गया है ; या
- (2) जब निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य क्रम में मिलती-जुलती वस्तुओं की बिक्री नहीं होती हो, या जब किसी खास बाजार स्थिति के कारण अथवा निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र के घरेलू बाजार में कम बिक्री के कारण उक्त बिक्रियों की समुचित तुलना नहीं की जा सकती हो, तब सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा।
- (क) उप धारा (6) के तहत निर्मित नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश अथवा क्षेत्र अथवा किसी उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किए जाने पर समान वस्तु का तुलनीय प्रतिनिधात्मक मूल्य ; अथवा
- (ख) उप धारा (6) के तहत निर्मित नियमों के अनुसार यथानिर्धारित मूल देश की कथित वस्तु की उत्पादन लागत जिसमें प्रशासनिक लागत, बिक्री लागत एवं सामान्य लागत और लाभ के लिए उचित राशि जोड़ी गई हो।

बशर्ते कि मूल देश से इतर किसी अन्य देश से उक्त वस्तु के आयात के मामले में जहां निर्यातक देश के जरिए वस्तु केवल जहाज से भेजी गई हो अथवा ऐसी वस्तु का निर्यातक देश में उत्पादन न होता हो अथवा निर्यातक देश में कोई तुलनीय कीमत न हो तो सामान्य कीमत का निर्धारण मूल देश में इसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

इस तर्क में दम नहीं है कि विश्व की विपणन एवं समर्थन लागत के कारण जर्मनी की सामान्य कीमत की तुलना भारतीय निर्यात कीमत के साथ नहीं की जा सकती है। दोनों बाजारों में (जर्मनी को घरेलू बाजार और भारत को निर्यात) बिक्री शर्तों में जो भी अंतर है उसमें

मात्र मूल्य समायोजन की जरूरत है। निर्यातक दोनों बाजारों, अर्थात् जर्मनी का घरेलू बाजार और भारत को निर्यात, की बिक्री शर्तों में अन्तर के कारण मूल्य समायोजन का दावा करने के पात्र होंगे। उपरोक्त के बावजूद निर्यातक ने कारखानागत वसूली की सूचना भेजी है और प्राधिकारी ने इस पर विश्वास किया है। इसलिए इस बारे में निर्यातक का दावा निरर्थक है।

18. यह कहना ठीक नहीं है कि विनिर्माण प्रक्रिया के बारे में प्रारम्भिक निष्कर्षों के पैरा एफ (4) में निकाला गया निष्कर्ष बिना किसी लिखित साक्ष्य के है। याचिकाकर्ता ने अपनी विनिर्माण प्रक्रिया का ब्यौरा गोपनीय आधार पर भेजा था और याचिकाकर्ता के कार्यालय और निर्माणस्थल का दौरा प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त एक अधिकारी दल द्वारा किया गया। चूंकि विनिर्माण प्रक्रिया का ब्यौरा गोपनीय आधार पर दिया गया था इसलिए इसे कुछ इच्छुक पार्टियों द्वारा निरीक्षण की गई सरकारी फाइल में उपलब्ध नहीं कराया गया।

19. याचिकाकर्ता द्वारा कोरिया में सामान्य कीमत न प्रस्तुत करने के मुद्दे पर प्रारम्भिक निष्कर्षों में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। याचिकाकर्ता ने अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद घरेलू बाजार में प्रचलित मूल्यों पर आधारित सामान्य कीमत प्रस्तुत करने में असमर्थता जताई है। इसलिए याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे कोरिया जनवादी गणराज्य के लिए निर्मित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करें। चूंकि प्राधिकारी ने प्रारम्भिक निष्कर्षों में कोरिया कुम्हो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना व साक्ष्य के आधार पर सामान्य कीमत निर्धारित करने की कार्रवाई की है, इसलिए इस समय इस बारे में यह तर्क अप्रासंगिक है।

20. सामान्य कीमत एवं निर्यात मूल्य राशि की घोषणा के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्यातक द्वारा दी गई गोपनीय सूचना के आधार पर तय की गई थी और इसलिए प्राधिकारी इसकी घोषणा करने से बचना चाहते हैं। प्राधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं कि विभिन्न ग्राहकों के लिए निर्यातक का अलग-अलग निर्यात मूल्य और/अथवा सामान्य मूल्य हो सकता है। इस प्रकार की वाणिज्यिक सूचना की घोषणा से निर्यातकों के वाणिज्यिक हितों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

(क) घरेलू बाजार में बिक्री मूल्य : निर्यातक ने दावा किया है कि उसने अपना उत्पाद...अमरीकी डालर प्रति मी. टन की कीमत पर घरेलू बाजार में बेचा था। प्राधिकारी ने पाया कि यह दावा प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं के लिए उसकी मूल्य सूची के आधार पर है। प्राधिकारी ने आगे और पाया कि निर्यातक ने तीन मूल्य स्तरों पर बिक्री की अर्थात् टायर विनिर्माताओं को, अन्य उपभोक्ताओं को और व्यापारियों को इन तीनों क्रेतावर्गों के मूल्यों में महत्वपूर्ण अन्तर था। यह भी पाया गया कि जांच अवधि के दौरान मूल्यों में वृद्धि हुई।

प्रारम्भिक अधिसूचना के संदर्भ में और निर्धारित प्रश्नावली में निर्यातक द्वारा दी गई सूचना में, निर्यातक ने उल्लेख किया है कि उसने जांच अवधि में अपने घरेलू बाजार में की बिक्री की, जिससे हुई निवल वसूली यू एस डालर..... की थी। प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक सूची कीमत के बजाय निवल बिक्री आय के आधार पर बिक्री कीमत का निर्धारण करना उचित समझता है।

प्राधिकारी ने बिक्री कीमत में निम्नलिखित समायोजना की अनुमति दी :

(i) कोरिया में की गई बिक्री पर अंतर्देशीय परिवहन : कंपनी ने अपने संयंत्रों से एक ही ट्रक में लादकर लाए गए परिवहन पर किए गए खर्च के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस साक्ष्य से यह पता चला कि कंपनी को मी. टन सामग्री की प्रति खेप के लिए बोन की सीमा तक व्यय करना पड़ा। जिनके परिणामस्वरूप यू एस डालर प्रति मी. टन का व्यय हुआ। तथापि कंपनी यह साक्ष्य देने में सफल नहीं रही है कि घरेलू बाजार में हुई इसकी सम्पूर्ण बिक्री पर परिवहन खर्च दर्शाई गई सीमा के अनुसार ही हुआ है। इस संबंध में दावाकृत सीमा तक समायोजन की अनुमति दी गई है।

(ii) शुल्क वापसी गणना : कंपनी ने यह उल्लेख किया कि चूंकि इसने ब्रुटाडीन को अपने स्रोत से प्राप्त किया है इसलिए इसे एक समान दर के आधार पर शुल्क वापसी (टैरिफ वापसी कहलाता है) के वापस भुगतान की अनुमति दी गई। कंपनी ने सीमाशुल्क के कार्यालय प्रशासन सं. 1996-15 की सूचना के अनुसार एक निर्यातक को वापस करने के लिए शुल्क दर की सूची के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इस सूचना के अनुसार, निर्यातक एन बी आर (के एन बी) 35 एल, के एन बी 35 एल एन, के एन बी 35 एच के निर्यात पर 3641 बोन (लगभग 5 यू एस डालर) की दर पर वापसी के लिए हकदार है।

चूंकि निर्यातक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य केवल इतना ही सुझाव देता है कि वह निर्यातों के मामले में शुल्क को वापसी का हकदार था और यह सिद्ध नहीं किया कि उसने इस सीमा तक वापसी का दावा किया और भुगतान प्राप्त किया। निर्यातक से दावों की प्राप्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया था। निर्यातक ने अपने वार्षिक लेखाओं से टैरिफ रिटर्न की एक प्रति प्रस्तुत की जो कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए टैरिफ रिटर्न का संकेत करती है, यह पाया गया कि कंपनी ने बोन की दर पर टैरिफ रिटर्न प्राप्त की। उपर्युक्त पर विचार करते हुए, प्राधिकारी शुल्क वापसी के लिए समायोजन की अनुमति देना उपयुक्त समझता है।

(iii) ग्राहकों के पास निरंतर दौर : याचिकाकर्ता ने यह बताया कि उसके लिए उनके विदेशी ग्राहकों के पास बार-बार जाना बहुत कठिन है। लेकिन घरेलू ग्राहकों के लिए उसका वाणिज्यिक और तकनीकी स्टाफ ग्राहकों के पास निरंतर दौर करेगा। यद्यपि निर्यातक ने इन क्रियाकलापों के लिए सही लागत की गणना करने में अपनी कठिनाई बताई है तो भी उसने इस संबंध में लगभग यू एस डालर प्रति मीटर के समायोजन का दावा किया है। निर्यातक ने आगे अपने लिखित अनुरोध में बताया है कि वह उस लागत के लिए अनेक प्रकार के साक्ष्य दिखाने का इच्छुक है जिसका हिस्सा वह अपने लेखा विभाग में रख रहा था प्राधिकारी ने

निर्यातक से निरंतर दौरे दर्शाने वाला साक्ष्य और उस दौरान स्थान विशेष पर जांच के समय उन पर किए गए खर्च का साक्ष्य प्रस्तुत करने का निवेदन किया है। निर्यातक यह संतोषजनक साक्ष्य देने में असफल रहा कि घरेलू बाजार में बिक्री के लिए उसे ग्राहकों के पास निरंतर दौरे करने पड़े।

निर्यातक इस बारे में संतोषजनक साक्ष्य देने में सफल नहीं रहा है कि उसने इस संबंध में लगभगयू एस डालर प्रति मी टन का व्यय किया है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में समायोजन अस्वीकार कर दिया गया है।

- (iv) **स्टोरेज और भंडारण :** निर्यातक ने यह दावा किया कि उसे अपने भंडारगृहों में अपने ग्राहकों को जरूरत को पूरा करने के लिए हमेशा कुछ उचित सामान रखना पड़ता है याचिकाकर्ता ने माल के लदान उतराई जिसकी लागत वोन है पर विचार करते हुए लगभग यू एस डालर प्रति मी टन के लदान और उतराई का दावा किया है। इसके अतिरिक्त निर्यातक ने एक महीने के लिए किग्रा के लिए वोन के भण्डारण व्यय पर विचार करते हुए लगभग यू एस डालर प्रति मी. टन के भण्डारण खर्च का दावा किया है। निर्यातक संतोषजनक साक्ष्य देने में असमर्थ रहा है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि भण्डारण एवं इसके रख-रखाव में उसने अमरीकी डालर प्रति मी. टन का औसत खर्च किया था। वास्तव में, निर्यातक ने कहा है कि परिकलन में कुछ त्रुटियां हुई हैं और वास्तविक खर्चा कम हुआ था अर्थात् भण्डारण पर अमरीकी डालर प्रति मी. टन और लदान और उतराई पर अमरीकी डालर प्रति मी. टन। प्राधिकारी भी यह बात नोट करते हैं कि निर्यातक ने वोन की राशि किराये के रूप में भुगतान की थी। संगत अवधि में घरेलू बिक्री पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने पाया कि निर्यातक ने भण्डारण पर लगभग अमरीकी डालर प्रति मी. टन का खर्चा किया था। यद्यपि निर्यातक लदान/उतराई और भण्डारण पर किए गए खर्च के बारे में अपने दावे को साबित नहीं कर पाया है, तथापि प्राधिकारी माह जनवरी 1995 में कम्पनी द्वारा वास्तविक रूप में भुगतान किए गए किग्रा को उस महीने की कुल घरेलू बिक्री से भाग देकर निकाली गयी अमरीकी डालर प्रति मी. टन की राशि के समायोजन को उचित मानते हैं।

- (v) **तकनीकी सेमीनार :** निर्यातक ने विभिन्न सेमीनारों पर एक वर्ष में किए गए अमरीकी डालर के खर्च का दावा किया है। तथापि प्राधिकारी ने पाया कि निर्यातक ने कोरिया के घरेलू बाजारों में के एन बी 35 एल एन बी आर की बिक्री के लिए लगाए गए तकनीकी सेमीनारों पर हुए पूरे खर्च का दावा किया है। निर्यातक द्वारा किया गया यह दावा सिद्ध नहीं किया गया है कि सेमीनार पर किए गए लागत खर्च का लगभग 70% के एन बी 35 एल लघु उपभोगताओं पर खर्च किया जायेगा।

इसलिए प्राधिकारी ने कम्पनी की कुल घरेलू बिक्री पर हुए इस खर्च पर विचार करते हुए तदनुसार दावे की अनुमति दे दी है।

- (vi) **ऋण शर्तें:—**कोरिया कुम्हो ने इस आशय का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उसने हमेशा अपने घरेलू बाजार में दिवसीय ऋण पर बिक्री की है। इसके अलावा, निर्यातक ने इस आशय का साक्ष्य भी नहीं दिखाया है कि उसकी ब्याज दर लगभग % प्रति वर्ष थी जैसा कि उसने दावा किया है। निर्यातक से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था कि वह अपनी औसत पूंजी लागत बताए, लेकिन इसने उक्त जानकारी भी प्रस्तुत नहीं की।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी इस बात पर विचार करते हैं कि घरेलू बाजार में ऋण आधार पर की गई बिक्री के बारे में निर्यातक का दावा अप्रमाणिक है।

उपरोक्त के रहते हुए, प्राधिकारी कम्पनी द्वारा धारित औसत ऋण और कम्पनी के वार्षिक लेखों के अनुसार औसत ब्याज दर के आधार पर अमरीकी डालर के समायोजन की अनुमति देना उचित समझते हैं।

22. पूर्व में दिए गए ब्याजों को छोड़कर प्राधिकारी संबंधित देशों में एन बी आर की सामान्य कीमत के निर्धारण के लिए अपनाई गयी क्रियाविधि के बारे में प्रारम्भिक निष्कर्ष के पैरा एच की पुष्टि करते हैं।

जी. निर्यात मूल्य

23. प्रारम्भिक निष्कर्षों के पैरा 1 के विवरण के अनुसार कारखानागत निर्यात मूल्य निकालने के लिए प्राधिकारी ने जिन समायोजनों की अनुमति दी है उनका जर्मनी के मामले में खण्डन नहीं किया गया है इसलिए उनकी पुष्टि की जाती है।

कोरिया कुम्हो के मामले में निर्यातक ने प्रमाण दिए हैं जिसमें यह दर्शाया गया है कि निर्यातक ने जिस सकल बिक्री वसूली की रिपोर्ट दी है वह एफ ओ बी बिक्री की वसूली है। निर्यातक ने आगे दावा किया है कि उसने ऋणरूप को कमीशन के रूप में, अपने संयंत्र से पत्तन तक अंतर्देशीय परिवहन एवं निरीक्षण शुल्क पर खर्चा किया है जिसकी लागत को एफ ओ बी बिक्री वसूली से पूरा किया गया। इसलिए एफ ओ बी बिक्री वसूली को कमीशन, अंतर्देशीय परिवहन एवं निरीक्षण शुल्क के लिए समायोजित करने की जरूरत है। निर्यातक ने ऋणरूप को दिए गए कमीशन के लिए एफ ओ बी मूल्य पर % की दर पर, अंतर्देशीय भाड़ा लगभग अमरीकी डालर प्रति मी. टन, एवं निरीक्षण शुल्क के लिए अमरीकी डालर प्रति मी. टन की दर से दावा किया है। प्राधिकारी ने एफ ओ बी बिक्री मूल्य का समायोजन निर्यातक द्वारा किए गए खर्च के साथ करते हुए कारखानागत वसूली

निकाली है। याचिकाकर्ता ने प्रारम्भिक निष्कर्षों के पहले भी दावा किया था कि कोरिया कुम्हो ने भारत को किए गए निर्यात पर दोहरे कमीशन का भुगतान किया है। किन्तु, प्राधिकारी ने इस दावे को प्रारम्भिक निष्कर्षों के समय अस्वीकार कर दिया था। प्राधिकारी के इस प्रश्न के उत्तर में निर्यातक ने पुष्टि की है कि उसने कुम्हो एण्ड कं. इंक को कमीशन का भुगतान नहीं किया है। निर्यातक ने कहा कि कुम्हो एण्ड कं. इंक के जरिए बिक्री मात्र इस उद्देश्य से की गयी थी कि वे अधिक निर्यात कारोबार का दावा कर सकें।

निर्यातक ने भारत को किए गए सभी निर्यातों के सभी संगत वाणिज्यिक बीजक उपलब्ध कराए हैं जिनकी जांच करने से स्पष्ट होता है कि सभी सामग्री का बीजक कुम्हो एण्ड कं. इंक द्वारा बनाया गया। यदि निर्यातक का यह दावा भी स्वीकार कर लिया जाता है कि कुम्हो एण्ड कं. इंक ने कोरिया कुम्हो से कोई कमीशन लिए बिना सामग्री की बिक्री की थी, तो भी प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि कुम्हो एण्ड कम्पनी इंक ने आवश्यक रूप से सामान की बिक्री के संबंध में बिक्री खर्च किया होगा जिसके लिए मूल्य समायोजन की जरूरत पड़ी होगी। तथापि प्राधिकारी ने खर्च की राशि का उल्लेख न होने के कारण इस बारे में कोई मूल्य समायोजन नहीं किया है।

24. पूर्ववर्ती ब्यौरे को छोड़कर प्राधिकारी निर्यात मूल्य के बारे में प्रारम्भिक निष्कर्षों के पैरा 1 की पुष्टि करते हैं।

एच. तुलना

25. उपरोक्त पैरा 13 के विवरण के अनुसार प्राधिकारी ने तुलनीय ग्रेडों के लिए निर्यात मूल्य की सामान्य मूल्य के साथ तुलना की है। उदाहरणस्वरूप, प्राधिकारी ने कोरिया कुम्हो से निर्यातित के एन बी 35 एल के निर्यात मूल्य की तुलना कोरिया के घरेलू बाजार में के एन बी 35 एल के सामान्य मूल्य से की है।

26. प्राधिकारी सभी संगत तर्कों पर विचार करने के बाद प्रारम्भिक निष्कर्षों के पैरा 2 पर सहमति व्यक्त करते हैं।

1. क्षति

मैसर्स ऋषिरूप ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के बारे में एच एस आर उत्पादन से संबंधित आर्थिक आंकड़े जैसे उत्पादन, स्टॉक, बिक्री की मात्रा एवं बिक्री मूल्य के आंकड़े उनकी टिप्पणियों के लिये उन्हें प्रदान करने चाहिए। प्राधिकारी ने नोट किया है कि ऋषिरूप द्वारा मांगी गई सूचनाएं वर्तमान जांच के लिए संगत नहीं हैं, और इसीलिए उनके अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने प्रारम्भिक निष्कर्षों के पैरा 4 के "क" में किमी एक मानदण्ड के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। प्राधिकारी ने प्रारम्भिक निष्कर्षों के पैरा [के (4) जी] में स्पष्ट तौर पर बताया है कि इस पैरा में दिए गए सभी पैरामीटर सामूहिक और संचयी स्वरूप से यह प्रमाणित करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसलिये यह मतलब निकालना गलत होगा कि केवल कुछ पैरामीटर ही घरेलू उद्योग की क्षति के कारण हैं।

ये तर्क कि कोरिया गणराज्य से निर्यात के कारण मूल्यों में गिरावट नहीं आई या इस तरह का कोई लिखित प्रमाण नहीं है जो यह दर्शाता हो कि जांच अवधि के दौरान कोरिया से आयातों में वृद्धि हुई है या जांच अवधि के दौरान कोरिया से आयात मूल्यों में कोई गिरावट नहीं आई है, इस बात का निर्णय करने के लिए असंगत हैं कि क्या घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। प्राधिकारी ने, जर्मनी और कोरिया गणराज्य से हुए आयातों से संचयी आधार पर हुई वास्तविक हानि की गणना नियमों के अनुसार की है।

27. यह तर्क कि जर्मनी और/या कोरिया से आयातों की पहुंच कीमतें याचिकाकर्ता की पहुंच कीमतों के समान ही हैं यह प्रमाणित नहीं करता है कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। इसके विपरीत, इससे यह निर्दिष्ट होता है कि घरेलू उद्योग को संबंधित देशों से आयात की पहुंच कीमत के समान कीमतों पर अपने माल को बेचने के लिए बाध्य किया गया (जो कि उस उचित कीमत से कम थी जो कि घरेलू उद्योग को मिलनी चाहिए थी)। घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मात्रा का आकलन करने के लिए आयातित माल की पहुंच कीमत की तुलना उस कीमत से करनी पड़ती है जो कि घरेलू उद्योग को मिलनी चाहिए थी।

28. प्रकाशित वार्षिक लेखों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि याचिकाकर्ता को कोई क्षति नहीं हुई है, विशेषकर उस स्थिति में जब कम्पनी कई प्रकार की गतिविधियों में लगी हुई है। प्राधिकारी ने प्रारम्भिक निष्कर्ष के पैरा के 4 (एफ) में स्पष्ट तौर पर बताया है कि याचिकाकर्ता को एन बी आर को उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचने से वित्तीय क्षति हुई है।

31. यह तर्क दिया गया है कि प्रारम्भिक निष्कर्षों और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध के बीच विरोधाभास है क्योंकि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसे कम मूल्य वर्धित गैर-एन बी आर मदें उत्पादित करने के लिए विवश किया गया है; जबकि प्राधिकारी का मानना है कि याचिकाकर्ता ने गैर-एन बी आर मदों की बिक्री एवं अपार लि. के व्यवसाय का स्थानांतरण होने के कारण उसे लाभ हुआ। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता का यह दावा है कि उसे अपने प्लांट पर, जो एन बी आर की मदों के उत्पादन के लिए है, कम मूल्यवर्धित गैर-एन बी आर मदें उत्पादित करने के लिए विवश किया गया है। प्राधिकारी का प्रारम्भिक निष्कर्षों में यह मानना है कि याचिकाकर्ता को गैर-एन बी आर मदों की बिक्री एवं अपार लि. का व्यवसाय स्थानांतरित होने के कारण लाभ हुआ। अपार लि., अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-एन बी आर मदों का उत्पादन करने में लगी हुई है जो कि याचिकाकर्ता द्वारा बेचे गई थी। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को उस गैर-एन बी आर व्यवसाय से हुए लाभ का उल्लेख किया था जिसे पुनर्वास पैकेज के एक हिस्से के रूप में याचिकाकर्ता को हस्तांतरित कर दिया गया था।

पाटन से भिन्न अन्य कारक जिनकी वजह से याचिकाकर्ता को क्षति हुई :

उपरोक्त पैरा ग—में, दिए गए पार्टियों के तर्कों पर प्राधिकारी ने विचार किया और यह पाया गया है कि :

32. जांच अवधि में याचिकाकर्ता के वास्तविक बिक्री मूल्य की तुलना जापान से हुए आयातों से संबंधित जांच में प्राधिकारी द्वारा निकाले गए उचित बिक्री मूल्य के साथ करना और यह मानना कि याचिकाकर्ता को कोई हानि हुई है, गलत होगा। उचित बिक्री मूल्य का सीधा संबंध अनेक पैरामीटरों से होता है जैसे कच्ची सामग्री का मूल्य, उपयोगिता एवं सेवा लागत जो समय-समय पर बदलती रहती है। चूंकि वर्तमान जांच और जापान से संबंधित जांच की अवधियां अलग-अलग हैं, इसलिए यह मानना गलत होगा कि उचित बिक्री मूल्य एक समान ही रहेगा।

33. चूंकि प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक निष्कर्षों में ये सही समझा गया है कि आयात की गई वस्तुओं और घरेलू सामान उत्पादों के मध्य प्रतियोगिता की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त है, इसलिए केवल कोरिया से आयातों का कोई औचित्य नहीं है।

35. यह स्पष्ट किया जाता है कि अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्कों की सिफारिश करते वक्त प्राधिकारी ने उचित बिक्री मूल्य के लिए केवल याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर ही निर्भर नहीं किया है। प्राधिकारी ने तत्काल वक्त पर जांच करने के लिए अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया और घरेलू उद्योग के लिए भारत में एन बी आर के उचित बिक्री मूल्य की गणना स्वतंत्र रूप से की है। प्राधिकारी ने सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धान्तों पर विचार करते हुए क्षमता उपयोग के इष्टतम स्तर पर उचित बिक्री मूल्य निर्धारित किया और इसके लिए पाटन से इतर मुद्रों को नगण्य माना है। चूंकि यह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गोपनीय आंकड़ों पर आधारित है इसलिए प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम के समय उसकी विस्तार से चर्चा नहीं की और इस जांच परिणाम में भी उसका उल्लेख नहीं किया है।

ऋषिरूप की इस दलील के संबंध में कि प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के क्षमता उपयोग पर कोई जांच परिणाम नहीं तैयार किया है, प्राधिकारी ने नोट किया है कि प्राधिकारी ने साफ तौर पर कहा था कि जहां तक एन बी आर का संबंध है, याचिकाकर्ता द्वारा अपनी क्षमता का उपयोग अब भी सृजित क्षमता से कम है। याचिकाकर्ता ने 6250 मी. टन एन बी आर की स्थापित क्षमता वाले एक संयंत्र से जांच अवधि में 1573.210 मी. टन एन बी आर का उत्पादन किया (और उपलब्ध क्षमता का उपयोग गैर एन बी आर मर्दों के उत्पादन के लिए किया)। इसलिए जांच अवधि के दौरान अकेले एन बी आर के रूप में याचिकाकर्ता का क्षमता उपयोग केवल 39.23% था।

36. इच्छुक पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों एवं इसके पूर्व की बातों पर विचार करने के बाद अधिकारी घरेलू उद्योग को हुई हानि से संबंधित प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा ट की पुष्टि कर सकते हैं।

37. याचिकाकर्ता के इस दावे के संबंध में कि उचित बिक्री कीमत की गणना किए गए उत्पादन के वास्तविक स्तर पर की जानी चाहिए थी, प्राधिकारी का विचार यह है कि, प्रचालनों के अधिकतम स्तर पर उचित बिक्री कीमत का निर्धारण करने से बाहरी कारण, अगर कोई हों, तो उनके प्रभाव समाप्त को जाएंगे।

कार्य-कारण संबंध

39. पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की वास्तविक क्षति हुई या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए अधिकारी ने निम्नांकित कारणों पर ध्यान दिया :—

(क) संदर्भित देशों से उत्पाद के संचयी आयात में सकल रूप से तथा भारत में उत्पाद के उत्पादन और उपभोग की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। कुल आयात में संदर्भित देशों के हिस्से में भी महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि घरेलू उद्योग ने महत्वपूर्ण स्तर पर बाजार खोया जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा ट (4) में दिया गया है।

(ख) संदर्भित देशों से एन बी आर के भारी आयात से घरेलू उद्योग को अपना उत्पाद अलाभकारी बिक्री कीमतों पर बेचना पड़ा जिससे कि वित्तीय हानि हुई।

40. सभी सम्बद्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इसकी पुष्टि करते हैं कि कोरिया आर सी और जर्मनी से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को संचयी रूप से नुकसान हुआ।

ट. अन्य मुद्दे

41. यह तर्क गलत है और कानून द्वारा इसका समर्थन नहीं होता है कि प्राधिकारी को प्रतिपाटन शुल्क निर्धारित करने के समय जांच पश्चात् अवधि के बारे में मामले की समीक्षा करनी चाहिए। अगर जांच अवधि के बाद की परिस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए कानून में विशिष्ट प्रावधान हैं। इस संबंध में विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग करने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि कुछ इच्छुक पक्ष (पक्षों) ने सुझाव दिया है। इसके बावजूद कि कानून में समीक्षा करने के विशिष्ट प्रावधान हैं, यह मुद्दा कि याचिकाकर्ता अभी 91000/- प्रति एम टी पर बिक्री कर रहा है या उसने जांच अवधि पश्चात् की अवधि में लाभ कमया है, की जांच उचित बिक्री कीमत के संदर्भ में की जाती है, जिसे सम्बद्ध अवधि में वसूली का याचिकाकर्ता को अधिकार है।

42. ऋषिरूप का यह तर्क कि अधिकारी ने इच्छुक पार्टियों द्वारा दी गई सूचना की गोपनीयता बनाए नहीं रखी, वह वास्तव में गलत है।

अधिकारी ने अपनी गैर-गोपनीय टिप्पणियों में ऋषिरूप द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत को भी पुनः प्रस्तुत किया है।

43. प्रतिपाटन शुल्कों का उद्देश्य किसी स्रोत से आयातों को प्रतिबंधित करने का नहीं है। इस प्रकार, यह कहना गलत होगा कि प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता किसी रूप में प्रभावित होगी। नियमों में यह व्यवस्था नहीं है कि याचिकाकर्ता या भारतीय उद्योग भी प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की स्थिति में देश की सम्पूर्ण मांग को पूरा कर पाएंगे।

44. वर्तमान कार्रवाई में याचिकाकर्ता के एकाधिकार स्थिति के बारे में भी तर्क अप्रासंगिक है चूंकि प्रतिपाटन अधिनियम के अंतर्गत किसी एक उत्पादक के अधिकार तब तक प्रतिबंधित नहीं किए जा सकते जब तक कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के मानदण्ड को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, यह देखा जाता है कि घरेलू उत्पादकों को विभिन्न स्रोतों के आयातों से सीधी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है और वे वास्तव में बाजार की कीमत के बारे में आदेश देने या उसे प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, प्रति-पाटन शुल्कों का उद्देश्य, जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणामों में विस्तृत विवरण दिया गया है, उस पाटन को खत्म करना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल करना है, न कि किसी विशेष स्रोत से आयातों को रोकना है।

45. पूर्ववर्ती विस्तृत विवरणों को छोड़कर अधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 8 की पुष्टि करते हैं।

47. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति की मात्रा का निर्धारण करने के लिए सीमाशुल्क का वर्तमान स्तर अप्रासंगिक है। चूंकि आयातों से घरेलू उद्योग को उन कीमतों पर क्षति हुई जिसमें सीमाशुल्क शामिल है, इसलिए प्रतिपाटन शुल्क के स्तर का निर्धारण करते समय सीमा-शुल्क पर विचार करना उपयुक्त है।

ठ. अन्तिम निष्कर्ष

48. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि :—

- * जर्मनी और कोरिया आर.पी. से निर्यात किए गए या वहां के उद्गम वाले एन.बी.आर. का भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया;
- * घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;
- * घरेलू उद्योग को यह क्षति जर्मनी तथा कोरिया आर.पी. के उद्गम वाले निर्यात या वहां से निर्यात किए जाने से हुई है।

49. इस प्रकार, अधिकारी प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 8 की पुष्टि करते हैं और अध्याय 40 के अन्तर्गत आने वाले एंक्वीलीनीटील बुटाडीन रबड़ (एन बी आर) के लेटेक्स रूप को छोड़कर सभी रूपों पर, जो कि जर्मनी और कोरिया आर.पी. के उद्गम वाला है या वहां से निर्यात किया गया है, निम्नांकित दरों पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं :—

देश और निर्यातक का नाम	शुल्क की राशि (रु. प्रति एम टी)
उद्गम वाला देश : जर्मनी	
बेयर ए.जी., जर्मनी	13255
उपर्युक्त को छोड़कर निर्यातक	13255
उद्गम वाला देश : कोरिया आर.पी.	
कोरिया कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लि.	8316
उपर्युक्त को छोड़कर निर्यातक	8316

50. उपर्युक्त के अधीन, अधिकारी दिनांक 30.12.1996 के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।

51. उपरोक्त अधिनियम के अनुसार, इस आदेश के खिलाफ अपील सीमाशुल्क, आयात और खर्च (नियंत्रक) अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास की जा सकती है।

दीपक चटर्जी, प्राधिकृत अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th July, 1997

Subject : Anti dumping investigation concerning imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) from Germany and Korea RP—final findings

9/1/95/ADD - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof :

A. PROCEDURE

1. The Procedure described below has been followed:

- i) The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) notified preliminary findings vide Notification no. 9/1/95/ADD dated the 30th Dec., 1996 and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;
- ii) Forwarding a copy of the preliminary findings, all known interested parties were requested to furnish their views, if any, on the preliminary findings within forty days of the date of the letter;
- iii) The Authority also forwarded a copy of the preliminary findings to the Embassy of the Federal Republic of Germany (hereinafter referred to as Germany) and the Republic of Korea (hereinafter referred to as Korea or Korea RP) in New Delhi with a request that the exporters and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings;
- iv) The Authority held a public hearing on 14th Feb., 1997 to hear views orally. All the parties attending the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were requested to offer their rebuttals. The following parties attended the hearing:
 - The petitioner, GAPL;
 - Shree Venkateshwara Ind.,
 - Parkman Polymer Ltd.,
 - All India Rubber Industries Association;
 - Inarco Ltd.,
 - Bayer (India) Ltd.,
 - Rishiroop Polymers Pvt. Ltd.,
 - Puneet Resins Ltd.,
 - Hyundai Petrochemical Company Ltd.,
 - Chemoplast,
 - Bombay Chemical & Rubber Products,
 - Kohinoor India,
 - CAPEXIL,
 - CDR Enterprises,
 - Micro Rubber,

- v) In accordance to Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to all the known interested parties. Comments received on the same have also been duly considered in these findings;
- vi) The views expressed by the exporters, importers and other interested parties involving common issues have not been repeated for the sake of brevity. The views expressed by various interested parties before the preliminary findings have also not been repeated for sake of brevity;
- vii) The investigations have been concluded within the time limit extended by the Central Government;
- viii) The Authority has suppressed confidential information in this notification. However, all the confidential information has been shown as "****" in this notification.

B. PETITIONER'S VIEWS

2. The petitioner made the following submissions on the preliminary findings:
 - a) Normal value and dumping margin in case of Korea RP are very low. Considering the export price and adjustments claimed by the exporter and the dumping margin arrived at by the Authority, the normal value in case of Korea Kumho comes to US \$ 1436.30. This normal value is prima facie suspect. The normal value, the cost of production and the export price should be scrutinised by the Authority, as the prices appear to be not recovering the full costs;
 - b) The Authority should consider dual commission in arriving at ex-works export price in case of Korea RP, as their sales are made through M/s. Kumho & Co. Inc., a group company of Korea Kumho;
 - c) The petitioner has made following comments on the fair selling price determined by the Authority for arriving at the amount of anti dumping duties:
 - The fair selling price should not be based on optimum level of capacity utilisation;
 - The cost of raw materials should be taken on the basis of the actuals;
 - The cost of utilities should be considered as variable costs;
 - The cost of direct labour should be considered as variable costs;
 - The cash discounts, etc. should be regarded as variable costs;
 - The landed cost to the consumer is relevant to determine fair selling price which should be compared to the landed cost of imports;
 - d) The petitioner is already meeting the requirement of the domestic market and has equivalents of the German and Korean grades imported from Korea Kumho, Bayer and Hyundai Petrochemical Company Ltd. (hereinafter referred to as Hyundai);
 - e) The Authority has not acceded to the request for non-consideration of customs duties while recommending the provisional anti dumping duties. The customs duty on NBR has been reduced from 52% to 42% in the Budget proposal for 1997. The domestic industry is therefore, facing renewed price pressure from the dumped imported NBR;
 - f) The claims made by Hyundai with regard to their prices in the domestic market and exports to India indicate that dumping exists in case of Hyundai also.

C. VIEWS OF EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

3. The importers and exporters have expressed their views, and the same are briefly mentioned below. The arguments expressed by the exporters and importers which are similar in nature have not been repeated for sake of brevity.

I EXPORTERS**a. Bayer AG, Germany:**

- i) The exporter extended its willingness to offer price undertaking as per rule 15 of the Rules supra and requested for suspension/ termination of the investigation in respect of the exporter;
- ii) The normal value in Germany cannot be compared with the prices at which the material was sold to India in view of marketing & support costs involved in case of sales in home market. A portion of the sale made by Bayer was to the wholesalers;
- iii) Bayer had introduced a new product, Perbunan NT 3445 during the investigation period and the export price during the investigation period were a reflection of standard industry practice of offering initially highly competitive prices for obtaining market approval;
- iv) The petitioner has alleged that the company has dumped during the investigation period. The petitioner has not contended that the dumping is continuing;
- v) The period of investigation is unusually short for such an investigation. The period coincided with the market introduction of a new type of NBR from Bayer and the prices at that time reflected the start up phase;
- vi) Bayer's average landed cost to the customer was similar to that of the petitioner;
- vii) No injury has been caused to the petitioner during the investigation period. This is apparent from the increase in production and reduction in stocks of the petitioner. Failure to utilize the installed capacities was a result of the short-comings of the petitioner themselves. The petitioner suffered because of increase in the prices of raw materials;
- viii) Inclusion of all types of NBR in the proposed order of imposition is unwarranted and exceeds the scope of the investigation in view of inability of the petitioner to produce certain types of NBR;
- ix) The table reproduced under J 1 of the preliminary findings is incomplete as it does not indicate the normal value and export price as the recital preceding it purports to suggest;
- x) The petitioner have themselves shown increase in their market share by 3 percent, whereas the Authority found a decline by 8 percent. Notwithstanding the fact that the claim of the petitioner is different from the finding of the Authority, the reduction per se does not establish that any injury has been caused to the petitioner;
- xi) The petitioner increased the prices by 10% in Oct., 1994 and by 52% so far since Sept., 1994. The petitioner has therefore not been forced to sell NBR at unremunerative prices;

xii) The petitioner is the only producer of NBR in India. No details of optimum cost of production and capacity utilization have been made available, which is important in view of other exports (from countries other than Germany) of NBR to India.

b. **Korea Kumho Petrochemical Company Ltd., Korea:**

The views expressed by Korea Kumho Petrochemical Company Ltd. (hereinafter referred to as Korea Kumho) directly as also through their representatives, M/s. Rishiroop Polymers Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as Rishiroop) are briefly as follows:

On like articles:

i) The Authority in its earlier findings relating to anti dumping investigation against Japan concluded that the non-Japanese NBR is not a "like-article" to the domestic NBR;

ii) NBR is not an article but refer to a generic term for a group of articles;

iii) NBR is available world-wide in various physical forms, such as solid forms (bale, sheet, powder), liquid forms (pure material, emulsified form as latex with water). The Authority has considered all physical forms of NBR as same, which is incorrect;

iv) With regard to the Authority's finding at para F(5) on substitutability, the burden of proof that Korean NBR grades are the same as petitioner's NBR grades lies on the petitioner;

v) The inference that Korean NBR is not a like article to the petitioner NBR can be drawn from the findings relating to Japan;

vi) The conclusion arrived at para F(3) of the preliminary findings that the various users have switched their requirement between domestic producer and overseas supplies is without any evidence on record or evidence not forwarded to Rishiroop for comments;

vii) The conclusion arrived at para F(4) of the preliminary findings relating to manufacturing process is without any evidence on record or evidence not forwarded to Rishiroop for comments.

On normal value and export price:

i) The petitioner has not furnished evidence in support of normal value in Korea;

ii) The Authority has not disclosed normal value and export price amounts in the preliminary findings;

iii) The Authority has not considered submissions made by Korea Kumho with regard to price adjustments and comparisons;

iv) The current export price to India or International prices indicate that there is no threat of material injury in future to the petitioner from Korean imports. The Authority has to consider all factors, including post investigation period factors, while recommending anti dumping duties. The Authority should review and update the matter at the time of determination of anti dumping duties. The petitioner is reported to have made profit of Rs. 139 lacs (1995-96) and Rs. 220 lacs (Apr.-Sept., 1996). The petitioner is at present selling at Rs. 91000 per MT ex-works. The Authority should utilise prudence and its discretionary powers to judiciously balance the interests of various interested parties.

On injury:

- i) No economic data for the investigation period were submitted by the petitioner at the time of filing petition;
- ii) There is no evidence of injury to the petitioner on the face of its balance sheet;
- iii) Landed cost of individual import transactions were higher than those claimed by the petitioner;
- iv) Part of NBR was imported for production of goods meant for export. The quantity of NBR imported for export production should be deducted from total imports for arriving at the quantum of imports from the subject countries. The imports for export production were made in a market where the petitioner is not competing for business;
- v) The petitioner's claim of price erosion is not supported by its balance sheet, which shows significantly higher selling prices;
- vi) There is a contradiction in the preliminary findings and submissions made by the petitioner in as much as the petitioner has claimed that it has been forced to produce low value addition non-NBR items, whereas the Authority has held that the petitioner reported profits because of sale of non-NBR items and transfer of business of Apar Ltd.;
- vii) Since the petitioner was already selling at Rs. 87500 per MT, which is higher than fair selling price worked out by the Authority in the investigation relating to imports from Japan, no further relief is required;
- viii) Exports from Korea have not resulted in price-undercutting in the Indian market;
- ix) The conclusion arrived at para K of the preliminary findings relating to injury determination is without any evidence on record or evidence not forwarded to Rishiroop for comments;
- x) There is no evidence on record to show that the imports from Korea only have increased during the investigation period by a substantial amount;
- xi) The Authority has erred in its conclusion that there was a decline in the CIF export price of NBR from Korea;
- xii) There is no evidence to show that the share of Korean imports in the total imports in India increased during the investigation period;
- xiii) The conclusion in para K4(d) with regard to selling prices is without any evidence on record;
- xiv) The Authority has not made any finding regarding capacity utilisation of the petitioner;
- xv) Factors other than alleged dumping should not be allowed by the Authority while arriving at the injury to the domestic industry. The following other factors caused injury to domestic industry:
 - a) Brought forward cumulative losses from previous financial year 1993-94;
 - b) Wrong location of plant by the petitioner. The plant is not closer to source of supply of Butadiene, resulting in higher cost of Butadiene to the extent of Rs. 1000 per MT;

- c) The consumption of electricity during the year 1994-95 was higher by 9.7% when compared to the standard consumption of 1215 KWH per MT;
- d) The petitioner should have produced one MT product per MT of raw materials consumed. The petitioner consumed 9607 MT raw materials and produced 8895 MT, resulting in wastage of approx. 547 MT of raw materials valued at Rs. 162.55 lacs during 1994-95.
- e) As per CEGAT order no. 148-154/97-A dated 4th Feb., 1997, the petitioner had low production during May and June, 1994, adjustment on account of which should be carried out by the Authority;
- f) The petitioner has a plant of small capacity. Generally, such plant internationally have a minimum installed capacity of 50000 MT to be viable. Analysis of annual report of the petitioner for 1994-95 reveals that its manufacturing cost to sales realisation ratio was 27.13% and raw materials cost to sales realisation ratio was 56.83%. In case the plant capacity were higher, then the cost of production would have reduced considerably.

All these factors listed above show that about Rs. 11210 per MT is the cause of injury to the petitioner by factors other than imports from Germany and/or Korea.

Others issues:

- i) As per Section 3(6) of the Customs Tariff Act, all provisions of Customs Act, 1962 are applicable to this investigation. Therefore, any complaint filed by the petitioner after expiry of six months from the end of March, 1995 is barred by the period of limitation as per Section 28 of the Customs Act. The petition against Germany is, therefore, time-barred. CEGAT judgement reported in Excise Law Times of 1990 (49) ELT 541 has also been cited by Rishiroop in this regard;
- ii) The petitioner lacks capacity to meet the entire demand of NBR in the country;
- iii) The Authority has erred in holding that the period of investigation considered is in accordance with the rules. There are no rules laid down with regard to the investigation period. Further, there is no rule compelling the Authority to investigate the period arbitrarily selected by the petitioner. Generally, a time period of one year is considered for the investigation;
- iv) The term "producers" in rule 2(b) of the Rules does not include "producer". It is evident from the rule 2(b) that there should be at least two producers in the domestic market so as to be considered as domestic industry. Since the petitioner is the only producer of NBR in India, it does not qualify as domestic industry;
- v) The petitioner alleged dumping of only bale form of NBR;
- vi) There is no evidence of written complaint against Korea;
- vii) The Authority has not maintained confidentiality of the information furnished by interested parties. The normal value in case of Korea Kumho can be worked out from the preliminary findings, wherein the Authority has disclosed the export price, the price adjustments and the dumping margin;
- viii) There are errors of facts in the preliminary findings with regard to views expressed by the interested party(ies) in respect of para C(c) (export price and price adjustments), C(d) (quantum of imports from Korea, K 4(a) (increase in quantum of imports from Korea), K 4(d) (decline in CIF export price). These errors of facts show non-application of mind and incorrect findings;

ix) The Authority has violated the principles of natural justice as the public hearing held on 12/6/1996 was not heard by Authority passing the order;

x) The jurisdiction of the Authority is limited to the identification of the article which is imported into India and which can be considered for anti dumping investigations;

xi) Economic data, such as production, stocks, sales volumes and selling prices of the petitioner with regard to HSR production should be forwarded to Rishiroop for comments;

xii) The Authority has wrongfully clubbed the imports from Germany and Korea RP to assess the injury to the domestic industry. In view of declining trend of imports from Korea RP, stable export price from Korea RP and no undercutting of prices by the exporters from Korea RP, it would be inappropriate to assess the injury to the domestic industry on cumulative basis;

xiii) Imposition of anti dumping duties would cause a lot of hardship to the consumers of NBR in India and their price competitiveness will be affected;

xiv) Powder or liquid type of NBR can not be made from the same plant and equipment where bale type of NBR is made;

c. **Hyundai Petrochemical Co., Ltd.:**

i) Hyundai claimed that it did not export any material during the investigation period and the company commenced commercial production only after the investigation period;

ii) The petitioner has not asked for imposing anti dumping duty on NBR exported by Hyundai;

iii) The landed price of exports from Hyundai is higher than ex-works price of the petitioner, considering the export price of US \$ 1475 at which the company has exported to India;

iv) Hyundai has sold to some of its customers in Korea at prices ranging from US \$ 1450-1500 per MT;

II. **IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTY(IES):**

i) The quality of NBR produced by the petitioner is inferior and inconsistent to the quality of NBR produced by the subject countries. The importers are compelled to import NBR from Japan even after imposition of anti dumping duty on NBR imported from Japan. This has increased their production costs. Imposition of anti dumping duty on imports from Germany and Korea would result in further deterioration of quality of NBR produced by the petitioner;

ii) The price comparison must be made with reference to the grade of NBR imported from the subject countries and sold by the petitioner. The comparison must be made with reference to the landed cost of the material to the consumers. The Authority has calculated dumping margin by comparing the average normal value in the domestic market in Korea and export price;

iii) The petitioner has increased its selling prices every time anti dumping duty has been levied;

iv) The charge of dumping is nearly two years old and levying anti dumping duty at this stage does not serve any purpose in view of changed conditions;

v) Imposition of anti dumping duty would not be in the interest of rubber industry and would affect exports in terms of price and quality;

vi) Demand of NBR in India is far in excess of the production of the petitioner, resulting in huge gap in the demand and supply in India. This would affect the interests of small scale units in the Country;

vii) Imposition of anti dumping duty would result in increase in the prices by the petitioner and snorlage of the goods in the market.

D. EXAMINATION BY AUTHORITY

4. The submissions made by the petitioner, exporters, importers and other interested parties have been examined and considered and, wherever appropriate, have been dealt hereinafter.

5. It is incorrect that there was no written complaint against Korea RP. The petitioner had very clearly, in response to Authority's letter mentioned that "Imports from Korea are at dumped prices". The petitioner provided the name(s) and address(es) of the exporter(s) in Korea RP, details of imports of NBR from Korea RP in absolute terms and relative to total imports and total consumption of NBR in India and other details relevant to determination of dumping by the exporters from Korea RP and/or injury to domestic industry. Since the petitioner had already provided other relevant details with regard to the investigation, the petition was considered as properly documented with regard to the Korea RP.

6. The Authority considers the price undertaking offered by Bayer AG as impracticable and, therefore, has proceeded with definitive determination in respect of Bayer AG.

7. The argument that the petitioner had not submitted any economic data at the time of filing of petition is without merit. The petitioner had submitted all necessary details required by the Authority, before the Authority proceeded with initiation.

8. There are no specific provisions in the Rules to suggest the period of investigation. There are, however, indirect references available to suggest that the period of investigations should not be less than six months. A period of six months is considered reasonable to investigate whether there was dumping, causing injury to the domestic industry, to warrant imposition of anti dumping duties.

9. The Rule regarding public hearing reads as under:-

"The Designated Authority may allow an interested party or its representative to present the information relevant to the investigation orally but such oral information shall be taken into consideration by the Designated Authority only when it is subsequently reproduced in writing"

The Authority notes that:-

- No party has a right to present information orally, unless allowed by the Authority;
- No cognisance can be taken of the oral information presented by a party unless the same is reproduced in writing.

The essence of the above Rule is that only written information can be considered by the Authority. Since written information furnished by various interested parties was already available to the Authority, the Authority considered it appropriate to proceed with preliminary findings without holding another public hearing. Notwithstanding the above, the Authority is consistently holding public hearings only after preliminary findings in all cases currently being investigated.

Moreover, the Authority granted a public hearing on 14 the Feb., 1997 and, therefore, the argument on this account deserves to be ignored.

10. With regard to the request made by Hyundai to exclude it from payment of anti dumping duties, the Authority notes that it would not be in accordance with the Rules to exclude Hyundai as the party did not export any material to India during investigation period. In fact, according to Hyundai, it commenced commercial production only after the investigation period. Since Hyundai did not export to India during the investigation period, it attracts Rule 22, which very clearly provides that the Authority may carry out a review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporter(s) or producer(s) who had not exported the product during the investigation period. Hyundai may, therefore, request the Authority for exclusion after conclusion of the investigations.

Since Hyundai has not exported NBR during the investigation period, the argument of the petitioner that the company dumped its NBR in the Indian market is without merits.

12. With regard to the argument of Bayer that the petitioner has not contended continued dumping from Germany, the Authority notes that the Authority has investigated whether the product under consideration has been dumped by the exporters from the subject countries during the investigation period. The Authority has not investigated dumping or injury in the post investigation period. If the conditions in the post investigation period have changed, any interested party may request for a review in accordance with the law. Further, it is incorrect to say that the petitioner has not contended continued dumping. The petitioner has in various letters requested the Authority for early investigation/ recommendation of anti dumping duties, pleading continuing dumping.
13. The period of six months is considered as a reasonable period for anti dumping investigations. While it is appreciated that the export prices of Bayer during the investigation period may be a reflection of introduction of a new product, the reasoning is irrelevant for anti dumping investigations.

E. DISCLOSURE OF ESSENTIAL FACTS MADE BY THE AUTHORITY:

a. Comments made by interested parties:

- i) M/s. Puneet Resins Ltd. argued in response to the disclosure made by the Authority that the calculation of landed price done by the Authority is incorrect. The actual handling charges are 3 percent, and not 2 percent, as considered by the Authority. M/s. Rishiroop argued that handling charges should be considered at 5 percent.
- ii) Deductions on account of advertisement cost, bad debts, donations, car expenses, and entertainment expenses should be made in the selling price in the domestic market as these expenses were incurred exclusively on domestic sales of all types of synthetic rubber.
- iii) Rishiroop argued that labor and utilities costs for the calculation of fair selling price should not be considered as variable cost. The party further argued that whether plant operates at 40% or 60% or 80% capacity, the additional costs for direct labor, power and other utilities such as steam do not increase or vary in the same proportion.
- iv) Bayer viewed that the petitioner enjoys a monopoly and the petition is an attempt to eliminate competition. The party has referred to the unaudited financial results (provisional) for six months ended on 30.9.1996, which indicates that the petitioner's profit increased in the first six months of 1996-97 as compared to the

corresponding period of 1995-96. The party has argued that in fact the petitioner is planning a huge expansion of their NBR capacity.

- v) Bayer argued that the reason for non-utilisation of capacity by the petitioner was shortage of the requisite raw materials at that time. The party has referred to the Annual Reports of the petitioner on this account.
- vi) It is not the purpose or function of the Authority to ensure a profit margin for the petitioner.
- vii) The petitioner has argued that:
 - In case of Korea RP, the exporter has incorrectly claimed price adjustments in the selling prices in the home market. The tariff return should be checked for actual return since the purchase of raw material is from the domestic sources.
 - Major sales of Korea Kumho is in the export market and, therefore, Korea Kumho should have incurred higher expenditure in customer visits abroad rather than in the local market.
 - Inland freight should not be considered since Korea Kumho has given its actual price realisations, which presumably is net of the inland freight. The petitioner has disputed the other claims of Korea Kumho with regard to price adjustments.
 - The comparison of ex-factory fair selling price with the landed value of imports is incorrect. While the fair selling price is ex-factory, the landed price is inclusive of dealer's commission and other costs. The one percent landing charges are not actually incurred by the importers in India and the same is considered only for the purpose of calculation of custom duties.

b. Examination of comments on disclosure of essential facts by the Authority:

- i) The Authority clarifies that it may not be appropriate to consider any new evidence/argument/submission made by interested parties at this stage. Therefore, only the submissions emanating from the essential facts made in the disclosure statement have been dealt with in this para.
- ii) Submissions with regard to calculations of handling charges, non-payment of landing charges, deductions on account of advertisement cost, bad debts, donations, car expenses, and entertainment expenses from the selling prices in the home market in case of Korea Kumho were not made earlier by the interested parties and are, therefore, rejected. In any event, if the information is considered as vital, an interested party may request review after closure of the investigations.
- iii) The argument of Rishiroop that whether plant operates at 40% or 60% or 80% capacity, the additional costs for direct labor, power and other utilities such as steam do not increase or vary in the same proportion is not denied. However, the Authority has compared actual capacity utilisation with the optimum level of capacity utilisation so as to consider whether a duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove the injury to the domestic industry.
- iv) As regards adjustment for the landing charges, the Authority consistently considers one percent landing charges and two percent handling charges for determination of landed value of imports. Regarding the claim of Rishiroop and Puneet Resins for 5% and 3% handling charges respectively, the Authority notes that determination of handling charges on the basis of handling charges on the basis of single import transaction may not be appropriate.

F. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

14. The product under consideration which has been investigated for dumping has been defined in the preliminary findings, which is Acrylonitrile Butadiene Rubber (also called Nitrile Rubber and NBR and referred to as NBR hereinafter), in all its forms except latex. The Authority notes that the articles imported originating from Germany and Korea RP were substitutable by the articles produced by the domestic industry -- both commercially and technically. The scope of the present investigation was defined in the notice of initiation. The petitioner also described the product being dumped as "Acrylonitrile Butadiene Rubber" or NBR and it would be incorrect to interpret that the petition was only for bale form of NBR.

A number of Interested party(ies) contended that a number of grades are not being manufactured in India. Rishiroop requested the Authority to exclude certain grades of NBR which were not imported in India during the investigation period. The Authority notes that only those grades can be exempted from the scope of the investigation which were not dumped during the investigation period. Since these grades were not imported in the investigation period, the fact of no-dumping is neither proved nor disproved. It would, therefore, be appropriate for the Authority to consider a specific request by an exporter for exclusion, provided it is demonstrated by the exporter that the grade under reference has not been exported to India at a price which would be lower of non-dump price and non-injurious price. Since Rishiroop made a request without establishing that the grades requested for exclusion were not dumped in India, the request of Rishiroop is rejected.

The Authority confirms paras E of the preliminary findings relating to product under consideration.

G. LIKE ARTICLES AND DOMESTIC INDUSTRY

15. The argument that the petitioner is not a domestic industry because the petitioner is the only producer of NBR in India is without merits. Rule 2(b) defines domestic industry as those domestic producers whose collective output constitute a major proportion of the total domestic production. In the absence of any specific provision to the contrary, the plural form of a noun shall also include its singular form and accordingly the term producers has to be interpreted as including its singular form also.
16. The argument that findings relating to anti dumping investigation against Japan concluded that the non-Japanese NBR were not like article to the domestic NBR is not supported by any argument or evidence. In any case, the observations made by the Authority in any particular case are based on the facts on record of that particular case and cannot be taken cognisance of in other cases.
17. The usage of the term "like article" under the rules refers both to a single article or a category of articles, since there is no provision in the law to suggest that "like article" does not apply to collective noun, as argued by Rishiroop.
18. NBR is made in various forms such as solid and liquid forms. It is, however, incorrect to say that the Authority has in the preliminary findings observed that all physical forms of NBR are same. Various forms of NBR merely require the authority to do comparison to the extent feasible of comparable forms/grades. The Authority is required, for instance, to compare import of KNB 35L NBR from Korea with the substitutable grade of the petitioner. Similarly, the comparison is required to be made between Perbunan NT 3445 grade of Bayer AG with the substitutable grade of

the petitioner. The Authority has not held in the preliminary findings that all grade of Bayer AG or Korea Kumho are substitutable with NT 3445 or KNB 35L

19. With regard to substitution of KNB 35L with other grades the Authority observes that the exporter has erred in interpreting the meaning of the term "like articles" under the Rules. The Authority has reproduced the definition of "like article" in the preliminary findings. Under Rule 2(d) "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such an article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the article under investigation.

The Authority notes that rule 2(d) does not imply that the imported goods from each of the subject countries and the goods produced by the domestic industry must have been substituted in order to qualify as "Like Article". Substitutability and not substitution is the key factor of the above definition in the instant case. The argument raised by the Interested parties on this account is not that the two goods are not substitutable.

Notwithstanding that substitutability and not substitution is of primary concern, there is evidence available to suggest that some of the importers had substituted their requirements between domestic produce, imports from Germany, Korea and Japan. For instance, M/s Sanjay International, Kohinoor, AV Industries, Hetampur, Gaurav International imported NBR from Korea Kumho as also from Germany and/or Japan. M/s. Basant Rubber has purchased NBR from Korea Kumho as also from the petitioner. Furthermore, the fact that the imports from Germany increased significantly during the investigation period as compared to the previous period clearly establishes that the increased imports substituted supplies made by other sources. The argument on this account is, therefore, rejected.

20. After considering all the arguments on this account, the Authority notes that the articles produced by the domestic industry have characteristics closely resembling those of article under investigation and therefore the criteria prescribed in the definition under rule 2(d) are adequately satisfied. The Authority confirms para F and G of the preliminary findings relating to like articles and domestic industry.

H. NORMAL VALUE

21. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

22. The argument that the normal value in Germany cannot be compared with the export price to India because of marketing and support cost is without merit. Any difference in terms and conditions of sale in the two markets (domestic market in Germany and exports to India) merely requires a price adjustment. The exporters are entitled to claim price adjustments on account of differences in terms and conditions of sale in the two markets i.e. domestic market in Germany and exports to India. Notwithstanding the above, the exporter has furnished ex-works realisations, which have been relied upon by the Authority, and therefore, the argument of the exporter on this account is without merit.
23. Except for the foregoing, the methodology adopted and adjustments allowed by the Authority in arriving at ex-works normal value, as detailed in the para H of the preliminary findings have not been controverted in case of Germany and are, therefore, confirmed.
24. It is incorrect to say that the conclusion arrived at para F(4) of the preliminary findings relating to manufacturing process is without any evidence on record. The petitioner submitted details of its manufacturing process on confidential basis and the office and works of petitioner were visited by a team of official deputed by the Authority. Since the manufacturing process details were furnished on confidential basis, the same were not made available in the public file inspected by some of the interested parties.
25. The issue with regard to non-submission of normal value in Korea by the petitioner has already been dealt in the preliminary findings. The petitioner pleaded its inability to furnish normal value based on the prices prevailing in the domestic market, in spite of its best efforts. The petitioner, therefore, requested the Authority to consider the normal value on the basis of cost of production constructed for Korea RP. Since the Authority has proceeded with determination of normal value on the basis of information and evidence made available by Korea Kumho, the argument on this account is irrelevant at this stage.
26. With regard to disclosure of the amount of normal value and export price, the Authority notes that the same are based on information furnished by the exporters on confidential basis and, therefore, the Authority refrains from disclosing the same. The Authority appreciates that the exporter may have different export price and/or normal value for different customers. Disclosure of such commercial information may seriously jeopardise the commercial interests of the exporters.
27. The Authority conducted on-the-spot investigation and verified the claims made by Korea Kumho. The normal value in case of Korea Kumho has been determined as detailed hereinbelow:

a) Selling Price in the Domestic Market: The exporter claimed that it sold in the domestic market at a price of US \$ *** per MT. The Authority found that the claim is based on its price list for direct customers. The Authority further found that the exporter sold at three price levels, i.e., to the tyre manufacturers, to other consumers and to the dealers. There was a significant variation in the prices to these three classes of buyers. It was also found that there was an increase in the price during the investigation period.

In response to the Initiation notification and in the information furnished by the exporter in the prescribed questionnaire, the exporter stated it had sold *** in its domestic market in the investigation period, net realizations from which was US \$ ***. The Authority considers it appropriate to determine selling price on the basis of net sales realization instead of one list price for arriving at the normal value.

b) The Authority has allowed the following price adjustments in the selling prices:

i) Inland transportation on sales made in Korea: The company produced evidence in the form of the transportation expenditure incurred by it in transporting one truck load from its plant. The evidence suggested that the company had to incur expenditure to the extent of Won *** per trip of *** MT material, resulting in an expenditure of US \$ *** per MT. Though the company has not been able to produce evidence that all its sales in the home market involved transportation expenditure to the extent shown, adjustment on this account to the extent claimed has been allowed.

ii) Duty drawback calculations: The company stated that since it has procured Butadiene captively, it has been allowed refund of duty drawback (called tariff return) on the basis of a flat rate. The company furnished evidence in the form of table of duty rate to be refunded to an exporter as per notice of the Office of Customs Administration No. 1996-15. According to this notice, an exporter was entitled for a refund at the rate of Won 3641 (approx. US\$ 5) on exports of NBR (KNB) 35L, KNB 35LN, KNB 35H.

Since the evidence furnished by the exporter merely suggests that it was entitled to a refund of duty in case of exports and did not establish that it claimed and received the drawback to this extent, the exporter was requested to furnish evidence of receipt of claim. The exporter furnished a copy of tariff returns from its annual accounts, which indicated tariff returns received by the company. It is found that the company received tariff returns @ Won ***.

In view of the above, the Authority considers it appropriate to allow adjustments on account of duty refund.

iii) Frequent Visits to the Customers: The petitioner stated that it is very difficult for them to visit their overseas customers frequently. But for domestic customers, its commercial and technical staff would visit the customers frequently. Though the exporter pleaded its difficulty to calculate the exact cost for these activities, yet it claimed an adjustment of approx. US\$ *** per MT on this account. The exporter further stated in its written submissions that it was willing to show various kind of evidence for cost which it was keeping in its accounting department.

The Authority requested the exporter to furnish evidence showing frequent visits and the amount of expenditure incurred thereon during on-the-spot investigation. The exporter has not been able to furnish satisfactory evidence to establish that sales in the domestic market involved frequent visits to the customers. Further, the exporter has also not been able to furnish satisfactory evidence to establish that it has incurred an expenditure of approx. US\$ *** per MT on this account.

In view of the above, the adjustment on this account is rejected.

iv) Storage and Warehousing: The exporter claimed that it has to always keep some reasonable inventory at its warehouses to provide for any need for material from its customers. The exporter has claimed loading and unloading of approx. US\$ *** per MT, considering loading/unloading of *** kgs, costing Won ***. Further, the exporter has claimed storage charges of approx. US\$ *** per MT, considering storage expenditure of Won *** for *** kgs. for one month.

The exporter has not been able to furnish satisfactory evidence to indicate that it had incurred an average expenditure of US\$ *** per MT, as claimed by Korea Kumho, on account of storage and handling. In fact, the exporter stated during on-the-spot investigation that there was some error in the calculation and the actual expenditure was lower, i.e., US \$ *** per MT on account of Storage and US \$ *** per MT on account of loading and unloading. The Authority, however, observes that the exporter had paid rent amounting to Won ***. Considering domestic sales in the corresponding period, the Authority found that total expenditure incurred by the exporter on warehousing was approx. US\$ *** per MT. Though the exporter has not been able to substantiate its claim with regard to expenditure on account of loading/unloading and storage, the Authority considers it appropriate to allow an adjustment of US\$ *** per MT worked out on the basis of rent actually paid by the company in the month of Jan., 1995 divided by the total domestic sales for that month.

v) Technical Seminar: The exporter claimed an expenditure of US\$ *** in a year on account of various seminars. The Authority, however, found that the exporter claimed the entire expenditure incurred on technical seminars towards sale of KNB 35L NBR in the domestic market in Korea. The claim of the exporter that about 70% of the cost incurred on seminar would be spent on small customers of KNB 35L is unsubstantiated.

The Authority has, therefore, considered this expenditure on the total domestic sales of the company and allowed the claim accordingly.

vi) Credit Terms: No evidence has been furnished by Korea Kumho that it has always sold on *** days credit in its domestic market. Further, no evidence has been shown by the exporter that its interest rate was about ***% p.a. as claimed by the exporter. The exporter was requested to indicate its average cost of capital, which was also not furnished.

In view of the above, the Authority considers that the claim of the exporter with regard to sale on credit in the domestic market is unsubstantiated.

Notwithstanding the above, the Authority has considered it appropriate to allow an adjustment on the basis of average credit held by the company and average rate of interest as per the annual accounts of the company.

28. Except as detailed in the foregoing, the Authority confirms the para H of the preliminary findings with regard to the procedure followed for determination of normal value of NBR in the subject countries.

1. EXPORT PRICE

29. The adjustments allowed by the Authority in arriving at ex-works export price, as detailed in the para I of the preliminary findings have not been controverted in case of Germany and are, therefore, confirmed.

30. In case of Korea Kumho, the exporter has shown evidence indicating that the net sales realization reported by the exporter were FOB sales realizations. The exporter further contended that it incurred expenditure on account of commission to Rishiroop, inland transportation from its plant to the port and inspection fee only, cost of which were met from the FOB sales realizations. The FOB sales realizations, therefore, require to be adjusted for commission, inland transportation and inspection fee. The exporter has claimed commission to Rishiroop @ ***% on FOB price, inland freight of US\$ *** per MT. and inspection fee of US\$ *** per MT. The

Authority has adjusted the FOB selling price with these expenditures, as claimed by the exporter, and arrived at ex-works realisations.

31. The petitioner had, even before preliminary findings, claimed that Korea Kumho has paid dual commission on its exports made to India. The Authority, however, did not accept this contention at the preliminary findings stage. In response to the query by the Authority, the exporter confirmed that it had not paid commission to Kumho & Co., Inc. The exporter stated that the sales have been made through Kumho & Co., Inc. merely to enable them to claim higher export turnover.

The exporter made available all relevant commercial invoices for exports made to India, scrutiny of which reveals that all the material was invoiced by Kumho & Co., Inc. Even if the argument of the exporter that Kumho & Co., Inc. sold the material without charging any commission from Korea Kumho is accepted, the Authority notes that Kumho & Co., Inc. must have necessarily incurred selling expenses incidental to sale of goods, warranting price adjustment. The Authority has, however, not made any price adjustment on this account in view of non-quantification of the expenditure.

32. Except as detailed in the foregoing, the Authority confirms the para I of the preliminary findings with regard to export price.

J. **COMPARISON**

33. As detailed in para 13 above, the Authority has made comparison of export price with normal value for the comparable grades. The Authority has, for instance, compared export price of KNB 35L exported by Korea Kumho with normal value of KNB 35L in the domestic market in Korea.
34. The Authority confirms the para J of the preliminary findings, after considering all relevant arguments on this account.

K. **INJURY**

35. Rishiroop argued that economic data with regard to HSR production such as production, stocks, sales volume and selling prices in respect of the petitioner should be supplied to them for their comments. The Authority notes that the information sought by Rishiroop is not relevant to the present investigation and, therefore, the request is rejected.
36. It is clarified that the Authority has not concluded on the basis of any single parameter in para K of the preliminary findings that the domestic industry has suffered material injury. The Authority has clearly stated in para K(4(g)) of the preliminary findings that production, capacity utilisation, sales quantities, average sales realisation, stock, losses (financial losses), all these parameters listed in this para collectively and cumulatively establish that the domestic industry has suffered injury.
37. The arguments that exports from Korea RP have not resulted in price-undercutting, or there is no evidence on record to show that the imports from Korea have increased during the investigation period or the import prices from Korea did not decline during the investigation period are irrelevant to decide whether domestic industry suffered material injury. The Authority has determined material injury from imports from Germany and Korea RP on cumulative basis in accordance with the rules.

38. The argument that landed price of imports from Germany and/or Korea were similar to that of the petitioner does not establish that the domestic industry has not suffered injury. On the contrary, it indicates that the domestic industry was forced to sell at the prices (which were lower than the fair price which the domestic industry ought to have realised) similar to the landed value of imports from the subject countries. In order to assess the extent of the injury suffered by the domestic industry, landed price of the imported goods has to be compared with the price which the domestic industry ought to have recovered.
39. It would be incorrect to hold, on the basis of published annual accounts, that the petitioner has not suffered injury, particularly in a situation when the company is engaged in a number of activities. The Authority has clearly brought out in para K4(f) of the preliminary findings that the petitioner has suffered financial losses from sale of NBR at prices below the cost of production.
40. It has been argued that there is a contradiction in the preliminary findings and submissions made by the petitioner in as much as the petitioner has claimed that it has been forced to produce low value addition non-NBR items, whereas the Authority has held that the petitioner reported profits because of sale of non-NBR items and transfer of business of Apar Ltd.;

It is clarified that the petitioner's claim is that it has been forced to produce low value addition non-NBR items at its plant meant for production of NBR. The Authority has held in the preliminary findings that the petitioner has reported profit because of sale of non-NBR items and transfer of business of Apar Ltd. Apar Ltd. is engaged, inter alia, in the business of manufacturing non-NBR items, which were sold by the petitioner. The Authority has referred to profitability of the petitioner from the business of non-NBR, which was transferred to the petitioner as a part of rehabilitation package.

41. **Factors other than dumping causing injury to the petitioner:** The arguments of the interested party(ies) with regard to factors other than dumping causing injury to the petitioner have been considered by the Authority and it is found that:

a) The Authority considers neither brought forward cumulative losses nor the retained earning while working out the amount of expenditure to be allowed on account of interest and profits.

b) The argument that plant location is wrong is without merits and is, therefore, rejected.

c) With regard to high consumption of electricity by the petitioners, it is clarified that the consumption norms mentioned by the petitioner in its annual accounts is on the basis of the actual production mix for that year and the same does not hold good for the production of NBR alone.

d) The argument with regard to excess consumption of raw materials is factually incorrect. The Authority has worked out cost of major raw materials, i.e., Acrylonitrile and Butadiene on the basis of consumption norms. Notwithstanding the fact that the Authority has not arrived at the cost of major raw materials on the basis of submissions of the petitioners alone, Rishiroop has not substantiated its argument that one MT Acrylonitrile and Butadiene are required for producing one MT of NBR.

e) It was clarified to the Hon'ble CEGAT also that there was a typographical error in the final findings notified by the Authority with regard to the anti dumping investigation against imports of NBR from Japan. The words May and June, 1994 should be read as May and June, 1993 in those final findings. The argument raised on this account is, therefore, rejected.

f) The argument with regard to small plant size of the petitioner resulting in high costs is unsubstantiated and, therefore, rejected.

42. Rishiroop argued that it would be appropriate to compare the actual selling price of the petitioner in the investigation period with fair selling price arrived at by the Authority in the investigation relating to imports from Japan and hold that the petitioner has not suffered injury. Fair selling price is directly linked to a number of parameters, such as prices of raw-materials, utilities and cost of services, all of which keep changing from time to time. Since the investigation period in the investigations relating to Japan and the present are different, it would be erroneous to hold that the fair selling price would remain the same.
43. Since the Authority considered it appropriate in the preliminary findings that the cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and like domestic produce, the imports from Korea alone have no relevance.
44. It is clarified that the Authority has not merely relied upon the submissions of the petitioner with regard to fair selling price while recommending provisional anti dumping duties. The Authority deputed a team of officials for conducting a detailed on-the-spot investigation and has independently worked out the fair selling price of NBR in India for the domestic industry. The Authority has determined fair selling price at optimum level of capacity utilisation after considering Generally Accepted Accounting Principles and effect of any factor other than dumping have been nullified. Since the fair selling price is based on confidential data furnished by the petitioner, the Authority refrained from discussing the details in the preliminary findings and the same are not disclosed in these findings also.

With regard to the contention of the petitioner that fair selling price ought to have been calculated at the actual level of production achieved, the Authority observes that working out fair selling price for the domestic industry at optimum level of operations will nullify the effects of extraneous factors, if any.

45. With regard to argument of Rishiroop that the Authority has not made any finding on capacity utilisation of the petitioner, the Authority notes that the Authority has very clearly stated that the utilisation of capacity by the petitioner in so far as NBR is concerned was still lower than the capacities created. The petitioner produced 1573.210 MT NBR during the period in a plant having installed capacity of 6250 MT p.a. NBR (and utilised the available capacity for production of non-NBR items). The capacity utilisation of the petitioner in terms of NBR alone during the period was, therefore, 50.34% only.
46. After considering the arguments raised by the interested parties and the foregoing the Authority confirms para K of the preliminary findings relating to injury to the domestic industry. The Authority further confirms that the cumulative assessment of injury is appropriate in the present circumstances.

L. CAUSAL LINK

47. In determining whether material injury to the domestic industry was caused by the dumped imports, the Authority took into account the following facts:
 - a) The imports of the product from the subject countries cumulatively increased significantly in absolute terms and relative to the production and consumption of the product in India. The share of the subject countries in the total imports also increased significantly. As a direct consequence, the domestic industry lost market to a significant level, which it would have otherwise gained;

b) The substantial imports of NBR from the subject countries forced the domestic industry to sell its produce at unremunerative prices, resulting in financial losses;

c) The trend of various parameters indicating injury to the domestic industry establish that the reasons for the same are the imports from the subject countries.

48. The Authority, after considering all related arguments, confirms that the injury to the domestic industry was caused cumulatively by dumped imports from Korea RP and Germany.

M. OTHER ISSUES

49. The argument that the Authority should review the matter with regard to post investigation period at the time of determination of anti dumping duties is incorrect and not supported by law. In case situation has significantly changed in the post investigation period, there are specific provisions in the law to take care of such situations. There is no provision in the law to use discretionary powers on this account, as suggested by some interested party(ies). Notwithstanding that there are specific provisions in the law to undertake review, the issue that the petitioner is at present selling at Rs. 91000/- per MT or has made profit in the post investigation period has to be examined with reference to the fair selling price which the petitioner is entitled to charge in the relevant period.
50. The argument of Rishiroop that the Authority has not maintained confidentiality of the information furnished by the interested parties is factually incorrect. The Authority has merely reproduced the export price claimed by Rishiroop in its submissions.
51. The purpose of anti dumping duties is not to restrict imports from any source. It would, therefore, be incorrect to say that imposition of anti dumping duties would in any way affect availability of the product to the consumers. The Rules do not provide that the petitioner or even the Indian industry should be in a position to meet the entire demand of the country in case anti dumping duties are to be levied.
52. Argument with regard to petitioner's monopoly position is also irrelevant in the present proceedings as the right of a single producer can not be restricted under the Anti Dumping Act, so long as the petitioner satisfies the criterion of domestic industry. Moreover, it is observed that the domestic producers are facing direct competition from imports from various sources and are not, in fact, in a position to dictate or manipulate the prices or the market. Moreover the purpose of anti-dumping duties, as detailed in the preliminary findings, is to remove dumping which has caused injury to the domestic industry and to re-establish a situation of fair competition and not to restrain imports from any specific source.
53. The present level of customs duties is irrelevant for determination of the extent of injury suffered by the domestic industry during the investigation period. Since the imports posed injury to the domestic industry at the prices inclusive of customs duties prevailing during the investigation period, it is appropriate to consider customs duties while arriving at the level of anti dumping duties.
54. Except as detailed in the foregoing, the Authority confirms the para L of the preliminary findings with regard to Indian Industry's Interest & Other Issues.

N. FINAL CONCLUSIONS

55. The Authority has, after considering the foregoing comes to the conclusion that:

- NBR originating in or exported from Germany and Korea RP has been exported to India below its normal value;
- the domestic industry has suffered material injury;
- the injury has been caused to the domestic industry by the exports originating in or exported from Germany and Korea RP.

56. The Authority, therefore, confirms para M of the preliminary findings and recommends imposition of definitive Anti-dumping Duties on all imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR), in all its form except latex, originating in or exported from Germany and Korea RP falling under chapter 40 at the following rates:

S No.	Name of the country and exporter	Amount of duty (Rs. per MT)
1.	<u>Country of origin : Germany</u> Bayer AG, Germany Exporters other than above	13255 13255
2.	<u>Country of origin : Korea RP</u> Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd. Exporters other than above	8316 8316

57. Subject to above, the Authority confirms the preliminary findings dated 30.12.1996.

58. An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

DIPAK CHATTERJEE, Designated Authority

